



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 11, 2015/पौष 21, 1936

No. 12]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 11, 2015/PAUSA 21, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2015

(अंतिम जाँच परिणाम)

विषय : आस्ट्रेलिया, ई. यू. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम।

फा. संख्या 14/1/2013-डीजीएडी : यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) से नियमावली के अंतर्गत एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ (ई. यू.) और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है।

2. यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर 12 जुलाई, 2013 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसे भारत के राजपत्र आसाधारण में प्रकाशित किया गया था और जिसके द्वारा नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने पर विचार किया जा सके।

क. प्रक्रिया

- इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित कथित पाटन के आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दूतावासों और भारत में ईयू का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल को अधिसूचित किया।

- प्राधिकारी ने जिसे भारत के राजपत्र आसाधारण में प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 2013 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी।
- प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों और औद्योगिक एसोसिएशनों (जिनके ब्योरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए) को इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति के साथ एक पत्र भेजा और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया।
- प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र की प्रतियां और निर्यातक प्र नावलियां भारत स्थित आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दूतावासों और भारतीय यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल को ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची सहित इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों संबद्ध देशों के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को भी विहित समय सीमाओं के भीतर प्रश्नावलियों का उत्तर देने की सलाह दें:
- प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी।
 - मै0 शेल कैमिकल्स, सिंगापुर
 - मै0 बायर पॉलीयूरीथेन एशिया(पीटीई) लि., सिंगापुर
 - मै0 बायर पॉलीयूरीथेन एशिया(पीटीई) लि., ईयू
 - मै0 रैपसोल क्रिमिका, एस.ए.,ईयू
 - मै0 डो कैमिकल (आस्ट्रेलिया) लिमिटेड डीएसीएल, आस्ट्रेलिया
- प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित के द्वारा दिया गया था:
 - मै0 शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. (एसईपीएल), सिंगापुर
 - मै0 शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि. (एसईपीएल), सिंगापुर
 - मै0 बायर (दक्षिण पूर्व एशिया) पीटीई लि., सिंगापुर
- तथापि, मौखिक सुनवाई के बाद एक संबद्ध देश अर्थात् आस्ट्रेलिया ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी थी जिनमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी:
 - मै0 शीला फोम पी लि.
 - मै0 प्राइम कमफर्ट्स
 - मै0 एम एच पॉलिमर्स पी लि.
 - मै0 सोमानी फोम लि.
 - मै0 तिरुपति फोम लि.
 - मै0 ड्युरा पफ
 - मै0 श्री सिंघल फोम्स पी. लि.
 - मै0 मल्टीवाइन फोम्स पी. लि.
 - मै0 श्री मालानी फोम्स पी. लि.
 - मै0 जॉय फोम प्रा0 लि.
- जाँच शुरुआत के बाद समय-सीमा के भीतर किसी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मौखिक सुनवाई के बाद, एक आयातक अर्थात् मै0 शीला फोम प्राइवेट लि. ने अपने कानूनी अनुरोध के साथ आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

- प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा।
- वाणिज्य आसूचना एवं सांयिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जांच अवधि और उससे पहले 3 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्योरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया और उसे प्राप्त किया गया तथा उन पर विश्वास किया गया।
- उत्पादन लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में रेखांकित दिशानिर्देशों की आलोक में क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई है। इस प्रकार परिकलित एनआईपी से यह पता लगाया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन और संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों/दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा की गई थी।
- पाटनपरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 12.9. 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का अवसर दिया था। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- यह जांच 1 जनवरी, 2012 से शुरू होकर 31 दिसम्बर, 2012 तक जांच अवधि (पीओआई) के लिए की गई थी। प्रवृत्तियों की जांच में हानि संबंधी वि लेषण के संदर्भ में अप्रैल 2009 - मार्च 2010, अप्रैल 2010 - मार्च 2011, अप्रैल 2011 - मार्च 2012 तथा जांच की यह अवधि शामिल है।
- जांच के पूरा होने की मूल तारीख 11.7.2014 तक की थी तथापि प्राधिकारी के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय द्वारा इस तारीख को 11.01.2015 तक बढ़ा दिया गया था।
- इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में इस जांच के अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच-परिणाम का आधार है, सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 3.1.2015 को जारी किया गया था। प्रकटन पश्चात् प्राप्त विवरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने तक इस प्रकटन विवरण में उन पर ध्यान दिया गया है।
- इस प्रकटन विवरण में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 53.69 रुपया के रूप में लिया गया है।

ख विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- सिंगापुर से प्रतिवादी निर्यातकों ने बताया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में केवल 3000 से 4000 अणु भार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल शामिल हैं। परंतु याचिका में एक आयात सौदे में यह भी दर्शाया गया है कि 5000 अणु भार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल के एक आयात सौदे को भी आयात आँकड़ों में शामिल किया गया है। प्रतिवादियों को यह आशंका है कि आयात आँकड़ों में अनेक ऐसे सौदे हो सकते हैं जो आयात के मात्रा को कॉफी बढ़ा देंगे और प्राधिकारी से उनकी जांच करने का अनुरोध किया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल है जो संबद्ध देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित एक पॉलिमर है संबद्ध उत्पाद 3000-4000 अणु भार का एक स्पष्ट लसिला तरल होता है जिसे प्रोपिलिन ऑक्साइड और एथिलिन ऑक्साइड के एक ट्रायल चैन स्टार्टर के पॉलिमराइजेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है।
- यह एक पॉलिथर है और उत्प्रेरकों और अभिवृद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करने पर साज समान, गद्दे, तकिये, मसनद, परिवहन सीटों और पैकिंग में प्रयुक्त पॉलियूरिथेन फोम उत्पादित करता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल को टैंकरों में या इस्पात के ट्रकों में परिवहन किया जाता है।

- फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में “प्लास्टिक और उनकी वस्तुएं” श्रेणी के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907.20 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और अभिलेख में सामग्री की जांच के आधार पर तथा विरोधी हितपक्ष पक्षकारों द्वारा 3000-4000 से अधिक अणु भार के एफएसपी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव को देखते हुए प्राधिकारी इस्पात की पुष्टि करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद '3000-4000 अणु भार का फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल' है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार कोड 3907.20 के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- सामान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
“समान वस्तु” से भारत में पाटित की जा रही जांच के अधीन वस्तु के समान या सभी प्रकार से उसके समरूप वस्तु अभिप्रेत है या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से समान न हो फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तु से अत्यंत मिलती-जुलती विशेषताएं हों।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ और दायरे के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पादन के समान वस्तु है।
- घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- आवेदक ने याचिका में दावा किया है कि वह भारत में समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है तथापि मै. एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स भारत में समान वस्तु के एक अन्य घरेलू उत्पादक है। यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि आवेदक ने याचिका में कहीं भी अपना नाम विनिर्दिष्ट नहीं किया है।
- प्राधिकारी के लिए संबद्ध उत्पाद की उस मात्रा की जांच करना अपेक्षित है जो मै. एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स द्वारा विनिर्मित की गई है या की जा सकती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आवेदक द्वारा ऐसी सूचना का प्रकटन याचिका में करना चाहिए था और प्राधिकारी को याचिका के अधूरे होने के कारण इस जांच को उचित ढंग से समाप्त कर देना चाहिए।

घरेलू उद्योग के विचार

- घरेलू उद्योग ने बताया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वे जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करने वाले एकमात्र उत्पादक हैं। किसी भी तरह से यह मानते हुए भी परंतु स्वीकार नहीं करते हुए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले अन्य उत्पादक भी हैं मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स नियम 2(ख) के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से का उत्पादन करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्पष्ट रूप से योग्य हैं।
- मै. एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि वे संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं करते हैं।
- यह भी बताया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई वर्तमान जांच पाटनरोधी नियमावली के पूर्णतः अनुपालन में हैं और इसलिए पूर्णतः जारी रखे जाने योग्य हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।”

- यह आवेदन मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार याचिकाकर्ता जांच अवधि में कुल घरेलू उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख हिस्से का उत्पादन करता है और इसलिए वह घरेलू उद्योग है क्योंकि नियम के अर्थ के भीतर योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करता है याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित किया है कि नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा या उसके किसी संबंधित पक्ष द्वारा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि वह नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है।
- रिकार्ड में साक्ष्य से यह भी नोट किया जाता है कि अन्य उत्पादक अर्थात् मै. एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स ने देश में कुल उत्पादन में पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु की नगण्य मात्रा का निर्माण किया है और यदि उस नगण्य मात्रा पर भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट है कि आवेदक की योग्यता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे फिर भी कुल घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से कहीं अधिक का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार “घरेलू उद्योग” और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत “योग्यता” संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

गोपनीयता

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:-
- याचिका में अत्यधिक गोपनीयता दर्शायी गई है। याचिका में याचिकाकर्ता की वितरण शृंखलाओं, कमीशन/ब्रूट नीति, ऋण शर्तें, सामान्य मूल्य परिकलन, खरीद नीति, बिक्री नीति, माल सूची और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आदि के संबंध में याचिकाकर्ता की नीति की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- आवेदक एक “सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी” के रूप में भी पंजीकृत है परंतु उसने अपनी वार्षिक रिपोर्टों पर गोपनीयता का दावा किया है। आवेदक द्वारा गोपनीयता के इस दावे का कोई कारण नहीं बताया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:-
- याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा प्रदत्त सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत इसकी अनुमति दी गई है और उस सूचना का सार्थक सारांश भी उपलब्ध कराए गए हैं। हितबद्ध पक्षों का यह दावा कि याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, निराधार है।
- दूसरी ओर, निर्यातकों द्वारा इतनी अधिक गोपनीयता का दावा किया गया है कि प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय अंश नियमों के अंतर्गत और जारी निर्देशों के अनुसार यथा अपेक्षित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय अंश का बिल्कुल सटिक रूपांतरण नहीं है।
- संबंधित कंपनियों की सूचना शेल ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा गोपनीय रखी गई है और प्राधिकारी को निर्यातक से सूचना निकलवानी पड़ी है।
- मात्रा से संबंधित सूचना भी निर्यातक द्वारा नहीं बतायी गई थी और उन्हें यह सूचना बतानी चाहिए। शेल और बायर ने भी इस बात का प्रकटन नहीं किया है कि ईयू की उनकी संबंधित कंपनियों ने भी भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था परंतु उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई है।
- दो सहयोगी निर्यातकों में से एक अर्थात् मै. बीएसईए ने अपने संबंधित उत्पादकों के नाम भी नहीं बताए हैं वे निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना देने में असमर्थ रहे हैं अतः घरेलू उद्योग के पास टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:-

i सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

ii हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे का पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई है। लागत निर्धारण संबंधी सूचना के प्रकटन नहीं होने के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी का यह मत है कि लागत निर्धारण और कीमत संबंधी सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है और सामान्यतः वह सारांश योग्य नहीं होती है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टें सार्वजनिक डोमेन में और आवेदन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षों का दावा वैध नहीं है और अस्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पुरजोर दलील दी है कि शेल ग्रुप ने अपनी संबंधित कंपनियों से संबंधित कतिपय मूल सूचना का खुलासा नहीं किया है यहां तक कि उन्होंने मात्रा से संबंधित सूचना को भी गोपनीय रखा है और प्रश्नावली के उत्तर में अधिकांश परिशिष्टों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है जिससे संबंधित पक्षों के लिए कोई सार्थक समझ नहीं विकसित हो पा रही है। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षों के गोपनीयता के दावों को, जहां भी आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षों को नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है।

ड. विविध अनुरोध

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितपक्ष पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत आवेदन विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत आवेदन पाटनरोधी करारके अनुच्छेद 5.2 के साक्ष्य संबंधी मानकों को भी पूरा नहीं करता है
- स्थान की अलाभकारी स्थिति के कारण, घरेलू उद्योग को उच्च संभार लागतों को वहन करना पड़ता है और इसलिए, उन्हें हुई क्षति स्थान के गलत चयन के कारण हुई है और न कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण
- घरेलू उद्योग प्रोपीलीन आक्साइड जैसी महत्वपूर्ण सामग्री को संभालने के लिए अवसंरचना के अभाव के कारण उच्च क्षमता उपयोग हासिल करने में असमर्थ है। इस कारक को याचिकाकर्ता की विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा, आस्थगन प्रतिबंध के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकता है।
- एक आयातक ने यह भी बताया है कि घरेलू उद्योग पर्याप्त गुणवत्ता और संगतता की संबद्ध वस्तु की आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- हितबद्ध पक्षों ने यह दलील भी दी है कि पाटनरोधी याचिका और रक्षोपाय जांच के बीच भी अंतर होता है अतः प्राधिकारी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात की जांच और सत्यापन करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने प्रपत्र के अनुसार, प्रपत्र IV ख में कहीं भी घरेलू उत्पाद की औसत बिक्री का कोई व्यौरा नहीं दिया है इसके अलावा याचिका में दिए गए सूची संख्याओं का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- यह संगत है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अमरीकी डॉलर के लिए अपनाई गयी विनिमय दर 53.69 रुपए हैं तथापि आरबीआई के अनुसार इस समय अमरीकी डॉलर की प्रचलित दर 61.10 रुपए हैं यह भी पूर्वानुमान है कि रुपए की कीमत फिर एक बार बढ़ेगी और उसके बाद गिर सकती है। इसका अर्थ है कि भारत में इस समय किए गए आयातों का कीमत निर्धारण जांच अवधि के दौरान उनके निर्धारण के तुलना में काफी अधिक है यह भी अनुरोध किया जाता है कि आवेदक घरेलू उद्योग 53.69 रुपए की विनिमय दर पर विचार करके 0-10 प्रतिशत की कीमत कटौती तक पहुंच गए हैं तथापि यदि वर्तमान विनिमय दर पर विचार किया जाए जो बिल्कुल सही तस्वीर प्रस्तुत करेगी, तो कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री समाप्त हो जाएगी।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों में हाथ से छोड़-छाड़ की गई है इसके अलावा प्रमाण पत्रों पर कोई तारीख दर्शायी नहीं गई है।
- आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग की है और इस प्रकार यह माना है कि उसे आयातों की कतिपय मात्रा के कारण क्षति हो रही है और न की कथत पाटित आयातों के कारण। इससे सिद्ध होता है कि भारत में संबद्ध वस्तु के पाटन का कोई मामला नहीं है।
- घरेलू उद्योग ने निर्यातकों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद आयात आंकड़ों का एक्सल वर्जन नहीं उपलब्ध कराया है।
- घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा अपनायी गई और निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के संबंध में सही सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- आयात मात्रा में वृद्धि भारत-सिंगापुर सीईसीए के सकारात्मक प्रभाव के कारण हुई है। अतः प्राधिकारी को कोई निर्धारण करने से पहले इस तथ्य पर विचार करना चाहिए।
- याचिका में कमी है और इसलिए जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- आयातकों को सहयोगी आयातक का व्यवहार पाने के लिए आयातक प्रश्नावली का उत्तर देना होता है। उत्तर न देना या अधूरा उत्तर देना किसी हितवद्ध पक्ष को अनुरोध करने के अधिकार से वंचित नहीं करता है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात पत्तन के आंकड़ें सही नहीं हैं क्योंकि उनमें अनेक आयात प्रविष्टियों की दोहरी गणना की गई है।
- घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 25000 मी. टन है जो भारत में कुल मांग का लगभग एक-तिहाई है। मांग और आपूर्ति में अंतर काफी अधिक है और इसलिए वर्तमान कार्रवाई को समाप्त कर देना चाहिए।
- घरेलू उद्योग को 1999 से व्यापार उपचारों का लाभ मिल रहा है और इसलिए इससे निर्भर उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को शुल्कों की सिफारिश कृपया नहीं करनी चाहिए।
- जहां तक बीएएसएफ और एसईपीएल/एसएसपीएल के बीच संबंध के मुद्दे का संबंध है निम्नलिखित अनुरोध किए जाते हैं:-
 - प्रोपलीन ऑक्साइड (पीओ) फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल' (एफएसपी) के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री है। अन्य के साथ एसईपीएल, पीओ को शेल श्रेया पॉयनीयर लिमिटेड (एसएसपीएल) से लेता है। एसएसपीएल, एसईपीएल की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसएसपीएल और बीएएसएफ साउथ ईस्ट एशिया पीटीई लिमिटेड (बीएएसएफ) संयुक्त रूप से एल्वा इस्टर्न पीटीई लिमिटेड जेवी (एल्वा) के मालिक है जो पीओ के निर्माण में भी शामिल है।
 - जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदन ने दलील दी है कि बीएएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां हैं क्योंकि एसईपीएल (एसएसपीएल की 100% धारक कंपनी के रूप में) और बीएएसएफ संयुक्त रूप से एल्वा के मालिक है आवेदक पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) को लागू करके इस दलील का समर्थन करता है जिसमें यह उल्लेख है कि उत्पादकों को यदि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को मिलकर नियंत्रित करते हैं तो निर्यातको या आयातकों से संबंधित माना जाएगा।
 - नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) जो स्पष्ट रूप से बताता है कि वह केवल "इस खंड के प्रयोजनार्थ" शब्दों द्वारा नियम 2(ख) पर लागू होता है और केवल नियम 2(ख) में दी गई "घरेलू उद्योग" की परिभाषा पर भी लागू होता है और किसी अन्य स्थिति पर नहीं। दूसरे शब्दों में नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) को इस कतिपय हास्यास्पद संकल्पना के समर्थन में प्रयोग किया जा सकता है कि बीएएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां हैं क्योंकि वे संयुक्त रूप से एल्वा के मालिक हैं नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) केवल इस बात के जांच के लिए लागू है क्या भारत में कोई घरेलू उत्पादक और सम्बद्ध देश में कोई निर्यातक एक दूसरे से संबंधित है। ऐसी

कोई दूसरी स्थिति नहीं है जिसपर नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) लागू होता हो क्योंकि यह संविधियों की व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांत "कानूनी कल्पना" की प्रकृति है।

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एआईआर 1955 एससी 661 में यह माना है कि कानूनी कल्पनाओं को उसी उद्देश्य तक सीमित रखना चाहिए जिनके लिए उनका सृजन हुआ है और उस वैध क्षेत्र से आगे उनका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीआईटी, बाम्बे बनाम अमरचंद एन. श्राफ एआईआर 1963 एससी 1448 और यूको बैंक बनाम राजेन्द्र लाल कपूर (2008) 5 एससीसी 257 सहित दिए गए अनेक निर्णयों में व्याख्या के सुस्थापित नियम की पुष्टि की है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों के आलोक में निर्देश प्राधिकारी को एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण होने के नाते पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) के प्रचालन के दायरे को केवल उन स्थितियों तक सीमित रखना होगा जहां वह इस बात की जांच करते हैं कि क्या भारत में कोई घरेलू उद्योग और सम्बद्ध देश में कोई निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित है। ऐसी कोई और स्थिति नहीं है जिसमें नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) लागू होगा और प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना उनकी शक्तियों और अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में उनके अधिदेश का घोर उल्लंघन होगा।
- अतः प्रतिवादी बताते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) को लागू करके बीएसएफ और एसईपीएल को संबंधित पक्ष नहीं माना जा सकता है।
- उपर्युक्त के अलावा प्रतिवादियों ने अपने निरंतर अनुरोधों को दोहराया है कि बीएसएफ और एसईपीएल संबंधित पक्ष नहीं है। इसके समर्थन में प्रतिवादि निम्नलिखित अनुरोध करते हैं:-
 - निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ई. यू., जापान और सिंगापुर और यूएसए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा में इन्हीं मुद्दों पर पहले भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बीएसएफ और एसईपीएल संबंधित पक्ष नहीं है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम का संगत उद्धरण निम्नानुसार है:-

"41. बीएसईए के पास अपनी खुद की एफएसपी विनिर्माण सुविधा नहीं है। प्रोपिलिन को ईएलएलबीए द्वारा खरीदा जाता है जो शेल और बीएसएफ की 50-50 संयुक्त उद्यम है और इसे पीओ में परिवर्तित करता है। आपूर्तिकर्ताओं का बीएसएफ से कोई कानूनी संबंध नहीं है और प्रोपिलिन को मौके पर आधार के अनुसार आंशिक रूप से प्रचलित बाजार दशाओं पर स्थानीय तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है। बीएसईए ने 2002 से एससीएसएल के साथ एक टोल व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके द्वारा बीएसईए, एससीएसएल को पीओ की आपूर्ति करेगा जो एफएसपी का उत्पादन करेगा और उसे वापस बीएसईए को भेजेगा। बीएसईए वार्षिक मात्रा के अंतिम निर्धारण तक पहुंचने तक एफएसपी की बढ़ती हुई मात्रा ले सकता है परन्तु वह टोल शुल्क जिसमें सभी वास्तविक लागत और आय की समुचित दर शामिल हो के अधीन होगा। यह व्यवस्था एफएसपी की पहली आपूर्ति के शुरू होने के बाद 7 वर्षों में समाप्त हो सकती है। बीएसईए अपनी खुद की विपणन व्यवस्थाओं के अनुसार और अलग-अलग ब्रांड नामों के अंतर्गत इस तैयार उत्पाद की बिक्री करता है। एसईपीएल और बीएसईए दो अलग-अलग विधिक सत्तायें हैं और इस व्यवस्था को छोड़कर उनमें कुछ भी साझा नहीं है।"

- 31 दिसम्बर, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टों में भी देखा जा सकता है कि बीएसएफ को एसईपीएल की संबंधित कंपनी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इससे यह तथ्य भी सिद्ध होता है कि एसईपीएल और बीएसएफ असंबंधित कंपनियां हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन्हें ऐसा ही माना जाना चाहिए।

- xx. उक्त अनुरोधों के मद्देनजर प्रतिवादी प्राधिकारी से आवेदक के उस तर्क को अस्वीकार करने का अनुरोध करते हैं कि इस तथ्य के कारण बीएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां हैं कि क्योंकि एसईपीएल (एसएसपीएल की 100% धारक कंपनी के रूप में) और बीएसएफ संयुक्त रूप से एलवा के मालिक हैं।
- xxi. आस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने बताया है कि आस्ट्रेलिया को जांच की शुरुआत की पूर्वसूचना प्राप्त नहीं हुई है कि आवेदन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आस्ट्रेलिया को यह जांच शुरू करने के निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
- xxii. आस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने यह भी बताया है कि उन विशेष परिस्थितियों जिनकी वजह से एक वर्ष के भीतर इस जांच को पूरा नहीं किया गया के कारण कौन से हैं।

घरेलू उद्योग के विचार

- वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने कतिपय मुद्दें उठाए हैं और हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों पर भी टिप्पणियां दी हैं जो निम्नानुसार हैं:
 - i. याचिका घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार दायर की गई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत की है और इसलिए वर्तमान कार्रवाई वर्तमान कानूनों के अनुसार वैध और न्यायोचित है।
 - ii. प्रमाणपत्रों को जांच की शुरुआत से पहले हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया गया था। घरेलू उद्योग ने फिर भी पुष्टि की है कि वे किसी निर्यातक, आयातक से संबंधित नहीं हैं या उन्होंने पूरी क्षति जांच अवधि में सम्बद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला संबंधित व्यक्ति हाथ से किए गए बदलाव के लिए पूर्णतः जिम्मेदार और उत्तरदायी है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि याचिका में प्रदत्त सूचना सही है और उसमें हितपक्ष पक्षों द्वारा किए गए दावों की तरह कोई विसंगति नहीं है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने नियमावली में विहित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।
- घरेलू उद्योग ने प्रपत्र IV क और क्षति विश्लेषण में बिक्री कीमत के पूरे व्यौरे दिए हैं। अतः एक स्थान पर सूचना को केवल पुनः प्रस्तुत न करना किसी नियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग ने क्षति विश्लेषण के समय कीमत कटौती की जानकारी अलग से दी है।
- घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को पूरे मूल आकड़ें उपलब्ध कराए हैं और पृथक्करण की पद्धति का विस्तृत व्यौरा दिया है तत्पश्चात् घरेलू उद्योग ने याचिका में जांच से संगत आंकड़ें भी उपलब्ध कराए हैं। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि सभी हितबद्ध पक्षों ने केवल अनुरोध किए हैं और उनके सही होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- मै0 शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. (एसईपीएल), मै0 शैल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि. (एसईटीएल) और मै0 बायर (दक्षिण पूर्व एशिया) पीटीई लि. द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों को हमें दिनांक 9 जनवरी, 2012 की व्यापार सूचना सं. 01/2012 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मूल प्रति में नहीं बताया गया। इसके अलावा मै0 शीला फोम्स ने समय सीमा के भीतर कोई लिखित अनुरोध नहीं किया था। पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अन्य समान मामलों जिनमें लिपिकीय त्रुटियों के कारण निर्यातक के पूरे उत्तर को अस्वीकार कर दिया गया, में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाये गए कड़े रवैये के अनुक्रम में हितबद्ध पक्षों के उत्तर को अस्वीकार करने का अनुरोध करता है।
- निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र डीजीएडी के विहित दिशानिर्देशों के अनुसार हस्ताक्षरित नहीं हैं। इसके अलावा सभी संबंधित पक्षों के पूरे पते भी प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में नहीं बताये गए हैं।
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सकरीन जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण की तर्ज पर मै0 शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. (एसईपीएल), मै0 शैल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि. (एसईटीएल) को असहयोगी निर्यातक माना जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध भी किया है कि सम्बद्ध वस्तु की पूरी मूल्य श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के पूरे उत्तर के माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के स्पष्ट निर्देश का पालन नहीं करने के लिए शैल के उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- शैल ने इस सूचना का भी छिपाया है कि वे बीएसएफ जो सम्बद्ध वस्तु का एक निर्यातक है से संबंधित है। उन्होंने प्रमुख कच्ची सामग्री के भी निर्माता के साथ अपने संबंध की सही स्थिति भी नहीं बताई है। इस कारक को देखते हुए भी प्राधिकारी को शैल की दोनों कंपनियों के निर्यातक प्रश्नावली के पूरे उत्तर को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- बायर साउथ ईस्ट एशिया (बायर) ने संबंधित उत्पादक के बारे में प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना नहीं दी है। इसकी अनुपस्थिति में बायर अलग पाटन मार्जिन का हकदार नहीं है। इस उत्तर को केवल इसी आधार पर सिरे से अस्वीकार किया जाए। इसके अलावा यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातक ने उस संबंधित विनिर्माता/उत्पादक का नाम भी नहीं बताया है जिससे उसने जांच अवधि में भारत को उसका निर्यात करने के लिए सम्बद्ध वस्तु खरीदी है।
- घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि शैल का निर्यातक प्रश्नावली उत्तर अस्वीकार हो जाता है तो प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार बायर का निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर स्वतः ही अस्वीकार हो जाता है। उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनेक मामलों में प्राधिकारी द्वारा अपनायी जा रही संगत प्रक्रिया पर विचार करते हुए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।

- इसके अलावा, सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण और शैल द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अगोपनीय अंश के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि बायर द्वारा निर्यातित पूरी सम्बद्ध वस्तु को उनसे घरेलू रूप से खरीदा गया है। पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने कहा है कि बायर के उत्तर को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग तकनीकी रूप से 50,000 मी. टन तक की सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन कर सकता है और उसमें सम्बद्ध देशों से बाजार में आ रहे कम कीमत के आयातों को छोड़कर कोई बाधा नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उनके पास सम्बद्ध वस्तु के विनिर्माण में आबद्ध रूप से उत्पादित प्रोपलिन ऑक्साइड (पीओ) का प्रयोग करने का लाभ है। इसके अलावा घरेलू उद्योग अपनी शेष जरूरत के लिए प्रोपलीन का आयात भी कर रहा है। अतः घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से हितबद्ध पक्षों के दावों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है क्योंकि उनमें कोई तथ्य नहीं है और वे रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।
- घरेलू उद्योग ने बताया है कि उनकी गुणवत्ता आयातित वस्तु के समतुल्य है और केवल कम कीमत के आयातों के कारण प्रयोक्ता उद्योग आयातित सम्बद्ध वस्तु को खरीद रहा है। घरेलू उद्योग के पास स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है।
- स्थान या भौगोलिक नुकसान के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि इन कारकों का पाटनरोधी जांच में कोई महत्व नहीं है क्योंकि कारखाना द्वार के पश्चात् सभी खर्चों पर किसी वि. लेपण में विचार नहीं किया जाता है। अतः किसी भाड़े या स्थान संबंधी नुकसान से संबंधित तर्क अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने बताया है कि पूर्ववर्ती मामलों के इतिहास में वर्तमान कार्रवाई के तथ्य से कोई कानूनी या वास्तविक संगतता नहीं है। प्राधिकारी के लिए केवल यह देखना अपेक्षित है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का मामला बनता है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी के दिमाग में केवल पक्षपात सृजित करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती जांचों का ब्यौरा दिया है।
- समान उत्पाद के लिए रक्षोपाय निदेशालय में जांच की शुरुआत के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह ऐसा पहला मामला नहीं है कि जिसमें समान उत्पाद के लिए दो जांचें एक साथ चल रही हैं। इसके अलावा यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा मामलों में दोनों जांचों के लिए जांच की अवधि अलग-अलग है। अतः किसी हितपक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग दोहरे संरक्षण की मांग नहीं कर रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि केवल दोनों शुल्कों में से अधिक को ही कारगर ढंग से लागू किया जाए। पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी से हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए दावों को अस्वीकार करने का अनुरोध है क्योंकि उनमें कोई तथ्य नहीं है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध भी करता है कि आंकड़ों का विश्लेषण करने में प्रयुक्त पद्धति में अंतर के कारण संख्याओं में कुछ अंतर हो सकता है।
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा और सम्बद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध भी करता है कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना नहीं दी है। इसके अलावा वे अपने दावे के समर्थन में कोई वास्तविक तथ्य देने में भी विफल रहे हैं। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है क्योंकि वे तथ्यों के विपरीत है।
- हितबद्ध पक्षों द्वारा सुझाई गए पद्धति की प्राधिकारी को वर्तमान विनिमय दर का प्रयोग करना चाहिए और किमत कटौती निर्धारित करनी चाहिए, गलत है और डीजीएडी की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न विविध मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा उनके संगत समझे जाने की निम्नानुसार जांच की गई है:
 - प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आस्ट्रेलियाई उच्चायोग को जांच की शुरुआत से पहले विधिवत् रूप से बताया गया था कि एक आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना को विभाग की वेबसाइट पर डाला गया था। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम उत्तरों/अनुरोधों की जटिलता के आधार पर जांच को पूरा करने के लिए 18 महीने तक का समय देते हैं।
 - रक्षोपाय जांच में उठाए गए मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को आयातों की कतिपय मात्रा से ही क्षति हो रही है और न की कथित पाटित आयातों के कारण, प्राधिकारी मानते हैं कि रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच की प्रकृति बिल्कुल अलग-अलग है और प्रत्येक अपने संबंधित नियमों द्वारा शासित होती है।
 - विरोधी हितबद्ध पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि याचिका में कमी और इसलिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई

थी जिनमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध दर्शाया गया था और अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत को उचित ठहराया गया था। विराम प्राधिकारी ने जब भी जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सूचना भी मांगी है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया है।

- प्रमाणपत्रों और समर्थन पत्र संबंधित तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि वह पूरे और सही है तथा उनमें कोई भी कमी नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया गया और केवल सत्यापित सूचना का प्रयोग जांच की अंतिम कार्रवाई के लिए किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में जरूरत के अनुसार सभी सूचना प्रदान की है और उनके आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।
- हितवद्ध पक्षों के अनुरोध के संबंध में की सिंगापुर से आयातों में वृद्धि दोनों देशों के बीच एफटीए के कारण हुई है, यह नोट किया जाता है कि इस तर्क का पाटनरोधी परिप्रेक्ष्य में कोई परिणाम या प्रासंगिकता नहीं है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब आयात पाटित हो और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों। अतः एफटीए के कारण आयातों में वृद्धि से संबंधित निर्यातकों/आयातकों द्वारा उठाए गए मुद्दे का इस जांच से कोई संबंध नहीं है।
- आयात आकड़ों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विश्लेषण के प्रयोजनार्थ डीजीसीआई एंड एस के आयात आकड़ों का प्रयोग किया है और इसलिए आयात आकड़ों की दोहरी गणना से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।
- कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए चालू विनिमय दर का प्रयोग करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तार्किक रूप से एक गलत धारणा होगी। चूंकि पूरी जांच एक अवधि विशेष से संबंधित है तो वर्तमान अवधि के लिए अलग से विनिमय दर के प्रभाव का वि-लेषण करना उचित नहीं होगा।
- जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है कि बीएसएफ और एसईपीएल/एसएसपीएल के बीच संबंध है और बीएसएफ ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसलिए एसईपीएल/एसएसपीएल को असहयोगी घोषित कर देना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने ईयू, जापान, सिंगापुर और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में पहले विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि बीएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां नहीं हैं। वर्तमान जांच में भी इन तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 31 दिसम्बर, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टों में भी देखा जा सकता है कि बीएसएफ को एसईपीएल की संबंधित कंपनी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इससे यह तथ्य भी सिद्ध होता है कि एसईपीएल और बीएसएफ असंबंधित कंपनियां हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन्हें ऐसा ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक के इस दावे में कोई तथ्य नहीं है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

26. वर्तमान मामले में, सिंगापुर से केवल निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है और निर्धारित ढंग तथा तरीके से अपने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

- मै. शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. (एसईपीएल)
- मै. शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि. (एसईटीएल), सिंगापुर
- मै. बायर (दक्षिण पूर्व एशिया) पीटीई लि., (बायर)

27. प्रश्नावली के उनके उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसईपीएल सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल है और पोलीओल के अन्य ग्रेडों का भी विनिर्माण करता है। एसईपीएल सम्बद्ध वस्तु की पूरी मात्रा को एसईपीएल के व्यापारिक स्कंध एसईटीएल को बेचता है। एसईटीएल, एसईपीएल की एक सहायक कंपनी है। एसईटीएल घरेलू बाजार में और भारत समेत निर्यात बाजारों को भी सम्बद्ध वस्तु को बेचता है। बायर ने भी भारत को निर्यात करने के लिए एसईटीएल से सम्बद्ध वस्तु की खरीद की है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग ने एसईपीएल/एसईटीएल द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए हैं और एसईपीएल/एसईटीएल द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।
- i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बीएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां हैं क्योंकि एसईपीएल (एसएसपीएल की 100% धारक कंपनी के रूप में) और बीएसईए एक तीसरी कंपनी है। एलबा इस्टर्न (पीटीई) लि. (ईएलएलबीए) में 50% प्रत्येक की शेयरधारिता संयुक्त रूप से रखते हैं। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) पर भरोसा किया है जिसमें यह बताया गया है कि उत्पादकों को यदि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को मिलकर नियंत्रित करते हैं तो निर्यातकों या आयातकों से संबंधित माना जाएगा।
 - ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शैल केमिकल सेराया (पीटीई) लि. (एससीएसएल), शैल सेराया पॉयनियर लि. (एसएसपीएल), एथिलिन ग्लायकोल सिंगापुर (ईजीएस) और एलबा इस्टर्न पीटीई लि. जेबी (एलबा) ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए मूल्य शृंखला पूरी नहीं है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि एसईपीएल और एसईटीएल के उत्तरों को भी अस्वीकार कर दिया जाए।
 - iii. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि एससीएसएल से एसईपीएल को आपूर्ति किये गए पीओ की कीमत अस्वीकृत होनी चाहिए और सही बाजार कीमत को अपनाया जाना चाहिए।
 - iv. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि एसएसपीएल द्वारा आपूर्ति किए गए पीओ को सही बाजार मूल्य पर लेना चाहिए क्योंकि एसएसपीएल, एसईपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
 - v. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि सिंगापुर में कौन सी कंपनी सम्बद्ध वस्तु का निर्माण कर रही है और क्या एससीएसएल या एसईटीएल द्वारा बायर/बीएसईए को सम्बद्ध वस्तु की आपूर्ति की जा रही है।
 - vi. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी कंपनी सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं की मालिक है।
 - vii. प्राधिकारी ने कास्ट एल्युमिनियम अलौय व्हील या अलौय रॉड व्हील की हाल में संपन्न हुई जांच में बहुत कड़ा रवैया अपनाया और इस आधार पर निर्यातक के उत्तर को अस्वीकार कर दिया कि उनकी मूल्य शृंखला पूरी नहीं है, संबंधित पक्षों की सूचना नहीं दी गई है, उत्पादक ने पुष्टि नहीं की है और यह कि एक भागीदार असंबंधित निर्यातक द्वारा निर्यातित मात्रा उनकी वस्तुएं हैं। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में भी उसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया है कि कोई अलग नीति स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगी।
 - viii. उत्पादक/निर्यातक ने प्रमुख कच्ची सामग्री के विनिर्माण में शामिल उनके संबंधित पक्षकारों के पूरे लागत निर्धारण को उपलब्ध नहीं कराकर प्राधिकारी को गुमराह किया है।
 - ix. सिंगापुर में सम्बद्ध वस्तु की स्थानीय खपत केवल लगभग 1500 मी. टन प्रतिवर्ष है जो जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए कुल निर्यातों के 5% से कम है। इस संदर्भ में यह अनुरोध भी किया जाता है कि शैल द्वारा कि गई घरेलू विक्रियां जो अंततः सिंगापुर से बाहर निर्यात कि गई, को उनकी स्थानीय विक्री नहीं माना जाना चाहिए।
 - x. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी का यह विचार है कि शैल अवधि अलग पाटन मार्जिन का हकदार है तो उस मामले में 80:20 परीक्षण परिकलित करते हुए प्राधिकारी को प्रोपलिन ऑक्साइड और एथलीन ऑक्साइड जैसी प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सिंगापुर से एक मात्र प्रतिवादी उत्पादक ने अपने संबंधित पक्षों को कच्ची सामग्री की लागत निर्धारण का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसी कच्ची सामग्रियां जो पास न हो की कीमतों को लागत परिकलन के परियोजनार्थ अस्वीकार किया जाना चाहिए।
 - xi. इयू और ऑस्ट्रेलिया से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भागीदारी नहीं की है और इसलिए प्राधिकारी को संगत प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए और निर्यात कीमत निर्धारित करना चाहिए।
 - xii. सभी संबंधित कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए मूल्य शृंखला पूरी नहीं है।

- xiii. यह स्पष्ट नहीं है कि सिंगापुर में कौन सी कंपनी सम्बद्ध वस्तु का निर्माण कर रही है और क्या सम्बद्ध वस्तु एसीएसएल या एसईटीएल द्वारा बायर/बीएसईए को आपूर्ति की जा रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं का स्वामित्व किस कंपनी के पास है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के विनिर्माण सुविधाएं एससीएसएल या एसईपीएल के स्वामित्व में हैं।
- xiv. यह स्पष्ट नहीं है कि किस कंपनी के पास सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं का स्वामित्व है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं का स्वामित्व एसीएसएल या एसईपीएल के पास है।

एसईपीएल और एसईटीएल द्वारा किये गए अनुरोध

29. एसईपीएल और एसईटीएल ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से संबंधित मुद्दों के संबंध में विस्तृत अनुरोध किये हैं जिनकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- एसईपीएल और एसईटीएल ने अनुरोध किया है कि बीएसईए और एसईपीएल को केवल इसलिए संबंधित नहीं माना जा सकता है कि एसईपीएल और बीएसईए संयुक्त रूप से एल्बा का स्वामित्व रखते हैं। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के लिए स्पष्टीकरण (ग) जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नियम 2(ख) में दी गई "घरेलू उद्योग" की परिभाषा केवल "इस खंड के प्रयोजनार्थ" पर ही लागू होती है और किसी अन्य स्थिति में नहीं क्योंकि संविधि के व्याख्या के सुविख्यात सिद्धांत के अनुसार यह "विधिक कल्पना" की प्रकृति का है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एआईआर 1955 एससी 661 में यह माना है कि कानूनी कल्पनाओं को उसी उद्देश्य तक सीमित रखना चाहिए जिनके लिए उनका सृजन हुआ है और उस वैध क्षेत्र से आगे उनका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।
- निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच के दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के जांच परिणामों में प्राधिकारी ने इन्हीं तथ्यों के अन्तर्गत पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि बीएसईए और एसईपीएल एक दूसरे से असंबंधित स्वतंत्र कंपनियों हैं।
- एसईपीएल सिंगापुर में अधिनियमित और पंजीकृत एक प्राइवेट लि. कंपनी है। एसईपीएल सिंगापुर में सम्बद्ध वस्तु का विनिर्माता है। एसईपीएल अपने संयंत्र में सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करता है।
- एसईपीएल संयंत्र के विनिर्माण कार्यकलाप उसकी 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मै. शैल कैमिकल्स सेराया (पीटीई) लि. (एससीएसएल) द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं यद्यपि एससीएसएल एक अलग विधिक सत्ता है परन्तु एसईपीएल द्वारा इसे एक पूर्णतः समेकित लागत केन्द्र माना जाता है और सिंगापुर के भीतर यह एसईपीएल के साथ एकल कर कंपनी है।
- संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी मुख्य कच्ची सामग्री प्रोपलिन ऑक्साइड (पीओ), एथीलिन ऑक्साइड (ईओ) और ग्लिसरीन होती है। पीओ संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री है (एफएसपी के भार का लगभग 90%)।
- पीओ को निम्नलिखित अनुपात में निम्नलिखित कंपनियों से एसईपीएल द्वारा खरीदा जाता है।

शैल कैमिकल्स सेराया (पीटीई) लि. (एससीएसएल)	लगभग ***%
शैल सेराया पॉयनियर लि. (एसएसपीएल)	लगभग ***%
बीएसएसएफ साउथ-ईस्ट एशिया पीटीई लि. (बीएसईए)	लगभग ***%

- संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि एससीएसएल पूर्णतः समेकित लागत केन्द्र है और उस लागत को अस्वीकार करने का कोई तर्काधार नहीं है जिसपर पीओ को एससीएसएल से एसईपीएल को हस्तांतरित किया गया और पीओ के लिए बाजार कीमत अपनायी जाए।
- एसएसपीएल से ईपीएल को आपूर्ति को किया गया पीओ एल्बा से खरीदा गया है। एल्बा, एसएसपीएल और बीएसईए के बीच एक 50-50 संयुक्त उद्यम है। एल्बा को एसएसपीएल द्वारा लागत केन्द्र माना जाता है। एल्बा इस लागत पर एसएसपीएल को पीओ का हस्तांतरण करती है। तत्पश्चात एसएसपीएल बाजार कीमत पर आधारित अंतरण निर्धारित कीमत पर एसईपीएल को पीओ का अंतरण करता है।

- ix. एसईपीएल और एसईटीएल ने प्राधिकारी को एससीएसएल, एसएसपीएल, ईजीएस और एलबा जो एफएसपी के उत्पादन से संबंधित है, के बारे में सभी सूचना प्रस्तुत की है। अतः घरेलू उद्योग का यह तर्क की मूल्य शृंखला पूरी नहीं है, गलत है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य अनुरोध

30. जांच की प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य अनुरोध किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें निम्नानुसार संगत माना गया है:

- क. आवेदक घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तु के विरुद्ध जांच शुरू करने की मांग की है परंतु उसके समर्थन में उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है फिर भी डीजीएडी ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि मूलभूत साक्ष्यात्मक मानकों को पूरा किए बिना कोई जांच व्यवहार्य नहीं है और इसलिए वर्तमान जांच को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।
- ख. संगत प्रावधानों में विनिर्दिष्ट दो शर्तों में घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित आंकड़ों की "अनुपलब्धता" को सामान्य मूल्य के परिकलन के आधार के रूप में शामिल करने का प्रावधान नहीं है। आवेदन में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए अपनाए गए उल्लिखित आधार त्रुटिपूर्ण है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त अंतरदेशीय भाड़े का अनुमान भी किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। आवेदक घरेलू उद्योग ने अंतरदेशीय भाड़े का अपना अनुमान बताने के लिए मनमाने ढंग से कुछ आंकड़े जात किए हैं। आवेदन में अंतरदेशीय भाड़े को जात किए जाने की पद्धति का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि संगत परिकलन क्या है।
- घ. याचिकाकर्ता द्वारा उसकी याचिका में जात सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी गणनाओं के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ङ. निर्यात कीमत के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए समायोजन असामान्य रूप से अधिक है और किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए प्राधिकारी को निर्यात कीमत की गणना करते समय सही समायोजनों का प्रयोग करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. अपने विभिन्न अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने एसईपीएल और एसईटीएल द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए हैं। जिन मुद्दों संगत समझा गया है उन पर निम्नानुसार विचार किया जा रहा है। निम्नवत निस्तारण किया गया है:

बीएसईए और एसईपीएल/एसईटीएल के बीच संबंध

32. जैसा कि ऊपर बताया गया है कि घरेलू उद्योग की इस दलील के संबंध में कि बीएसएसएफ और बीएसईए और एसईपीएल/एसएसपीएल के बीच संबंध है और बीएसएसएफ ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए एसईपीएल/एसएसपीएल को असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने ईयू, जापान, सिंगापुर और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में पहले विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि बीएसएसएफ और एसईपीएल संबंधित कंपनियां नहीं हैं। वर्तमान जांच में भी इन तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक के इस दावे में कोई तथ्य नहीं है।

33. घरेलू उद्योग के इस दो के संबंध में कि सभी संबद्ध पक्षकारों ने निर्यात प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इसलिए मूल्य शृंखला पूरी नहीं हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा दावा किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का विनिर्माण एसईपीएल द्वारा किया जाता है और एसईटीएल द्वारा उसकी बिक्री की जाती है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण कार्यों का प्रबंधन एसईपीएल की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी एससीएसएल द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की बिक्री शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस), एसईटीएल के स्वामित्व वाले एक पंजीकृत व्यवसाय द्वारा की जाती है। यद्यपि एसईपीएल और एसईटीएल ने ईक्यूआर दायर किए हैं वहीं दिनांक 12.09.2014 को सार्वजनिक सुनवाई के समय प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद एससीएसएल और शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) द्वारा ईक्यूआर दायर नहीं किए गए हैं। शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) और एसईएसएल, द्वारा ईक्यूआर दायर न किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी (i) भारत को निर्यातित सम्बद्ध वस्तु की वास्तविक निर्यात कीमत (ii) घरेलू बिक्रियों की वास्तविक बिक्री कीमत (iii) सम्बद्ध वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत और (iv) सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन पश्चात आवागमन निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन और उसकी बिक्री की संपूर्ण मूल्य शृंखला के अभाव में प्राधिकारी ने एसईपीएल और एसईटीएल द्वारा दायर ईक्यूआर को नामंजूर कर दिया है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

34. अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

आस्ट्रेलिया के उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य

35. चूंकि आस्ट्रेलिया से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और जांच अवधि के दौरान आस्ट्रेलिया में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य से संबंधित कोई सूचना हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही सार्वजनिक डोमेन में देखी जा सकती है इसलिए आस्ट्रेलिया में उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और तर्कसंगत लाभों को जोड़कर घरेलू उद्योग के बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों समेत विधिवत रूप से समायोजित करके परिकल्पित लागत उत्पादन के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। प्राधिकारी द्वारा आस्ट्रेलिया के इस प्रकार निर्धारित किए जाने के लिए प्रस्तावित सामान्य मूल्य निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ईयू के उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य

36. चूंकि ईयू से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और जांच अवधि के दौरान ईयू में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य से संबंधित कोई सूचना हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही सार्वजनिक डोमेन में देखी जा सकती है इसलिए ईयू में उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और तर्कसंगत लाभों को जोड़कर घरेलू उद्योग के बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों समेत विधिवत रूप से समायोजित करके परिकल्पित लागत उत्पादन के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। प्राधिकारी द्वारा ईयू के इस प्रकार निर्धारित किए जाने के लिए प्रस्तावित सामान्य मूल्य निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर के उत्पादकों तथा निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य

37. जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है कि एसईपीएल/एसईटीएल के संबद्ध पक्षकारों द्वारा ईक्यूआर ने भरे जाने के कारण प्राधिकारी ने उनके द्वारा भरी गई ईक्यूआर नामंजूर कर दी। चूंकि संबद्ध वस्तु का एसईपीएल के अलावा कोई अन्य उत्पादक नहीं है इसलिए सिंगापुर के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विनिर्मित उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत और पैकेजिंग लागत सहित विधिवत समायोजन करके तर्कसंगत लाभ जोड़कर किया है। प्राधिकारी द्वारा इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत

38. आस्ट्रेलिया से किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारण की गई है। प्राधिकारी ने एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात मूल्य का आकलन करने के लिए दावों के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्रीबीमा, पत्तन प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, बैंक प्रभार का समायोजन किया। तदनुसार, ऑस्ट्रेलिया के मामलों में एक्स फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ईयू से उत्पादकों तथा निर्यातकों के मामले में निर्यात मूल्य

39. ईयू से किसी निर्यातक/उत्पादक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त को देखते हुए, ईयू के उत्पादकों/निर्यातकों के मामलों में रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई थी। प्राधिकारी ने एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्रीबीमा, पत्तन प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, बैंक प्रभार का समायोजन किया। तदनुसार, ईयू के मामलों में एक्स फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में निर्यात मूल्य

40. एसईपीएल/एसईटीएल ने जांच की अवधि के दौरान अपने पंजीकृत बिजनेस अर्थात शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) के जरिए भारत सहित कई देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि संबद्ध पक्षकारों द्वारा ईक्यूआर न भरे जाने और पूर्ण मूल्य शृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी ने एसईपीएल/एसईटीएल द्वारा दायर ईक्यूआर को अस्वीकार कर दिया।

41. बेयर ने जांच के दौरान अपने ब्रांड नाम आरकोल पोल्योल 5613 से भारत को संबद्ध वस्तु (बल्क तथा पैकड दोनों) का *** एमटी निर्यात किया था जिसका कुल मूल्य *** यूएस डॉलर था। निर्यातक ने उधार लागत, ओवरसीज भाड़ा, बीमा, सर्वेयर फीस, ड्रम्स की लागत, ड्रमिंग कॉस्ट, बेयर हाउसिंग एण्ड हेंडलिंग, अंतरदेशीय भाड़ा, स्टोरेज एवं बैंक प्रभार के लिए *** यूएस डॉलर के समायोजन का दावा किया था। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस से एकत्रित आयात डाटा के आधार पर यह नोट किया कि लगभग *** एमटी आरकोल पोल्योल 5613 का सिंगापुर से निर्यात किया गया था जबकि बेयर साऊथ ईस्ट पीटी लि. द्वारा रिपोर्टेड निर्यात की मात्रा डीजीसीआई एण्ड एस के डाटा में रिपोर्टेड उनकी ब्रांडेड संबद्ध वस्तु की निर्यात की मात्रा से काफी भिन्न थी। अतः प्राधिकारी ने बेयर द्वारा फाईल किए गए प्रश्नावली को खारिज कर दिया।

42. चूंकि किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यात ने ईक्यूआर दायर नहीं की इसलिए सिंगापुर से किए गए निर्यातों की निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार की गई है। प्राधिकारी ने फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए कैमिशन, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा और पत्तन प्रहस्तन प्रभार के कारण समायोजन किया है। तदनुसार फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

43. संबद्ध वस्तु के लिए उपरोक्त निर्धारित अनुसार सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है –

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/एमटी)	निवल निर्यात मूल्य (यूएस डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
आस्ट्रेलिया	कोई भी	कोई भी	***	***	***	***	30-40
यूरोपियन यूनियन	कोई भी	कोई भी	***	***	***	***	30-40
सिंगापुर	कोई भी	कोई भी	***	***	***	***	0-10

क्षति मूल्यांकन तथा क्षति और आकस्मिक कारक के लिए प्रणाली

उत्पादों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. इस जांच के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध तथा जो अधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए, वे निम्न प्रकार हैं –

- डीजीएडी के लिए न केवल याचिकाकर्ता कंपनी बल्कि बाजार में अन्य घरेलू उत्पादकों के आंकड़ों की भी जांच करनी आवश्यक थी। इस मामले में, डीजीएडी को क्षति के मूल्यांकन के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए था कि वे अन्य उत्पादकों के बारे में जानकारी दें या अन्य घरेलू उत्पादकों को अनिवार्य करना चाहिए था कि वे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं।
- आधार वर्ष की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान आयात मूल्य में वृद्धि हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह दावा तर्कसंगत नहीं है कि पाटित किए गए और कम मूल्य के आयात लाभ को प्रभावित कर रहे हैं तथा विक्रय मूल्य बढ़ाने में वे असमर्थ हैं। यह भी उल्लेख है कि किसी प्रकार भी वस्तुओं की मात्रा पर प्रभावित नहीं थी।
- यह भी उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग ने आर्टिकल 3.4 के संबंध में अनिवार्यता पूरी नहीं की थी जो यह अनिवार्य करता है कि कई कारणों से 'वास्तविक और संभावित' में गिरावट की जांच की जाए तथा क्षति का सकारात्मक निर्णय दिया जाए।
- घरेलू उद्योग को इसकी संयंत्र क्षमता बढ़ाने तथा क्रिटीकल कच्चा माल संभालने में अक्षमता के कारण क्षति का सामना करना पड़ा था तथा इसीलिए क्षति को सिंगापुर से निर्यात के कारण नहीं कहा जा सकता।
- घरेलू उद्योग हर वर्ष उत्पादित वस्तुओं का 98-99 प्रतिशत बेचने में समर्थ था। उस स्थिति में आवेदक घरेलू उत्पादक के पास उपलब्ध सामान सूची याचिका में दी गई इनफ्लेटेड सूची की तुलना में काफी कम होनी चाहिए।

- घरेलू उद्योग यह आरोप लगा रहे हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात काफी अधिक है तथा घरेलू उद्योग के कार्य कलापों को बाधित कर रहा है। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग कुल मांग का औसत 25-30 प्रतिशत ही पूरा कर पा रहा है। क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत होने पर भी यह कुल मांग का 40 प्रतिशत ही पूरा कर पा रहा है।
- जबकि एक आस्ट्रेलिया के निर्माता जिसने भारत को बहुत कम निर्यात किया था, उस कम्पनी ने आस्ट्रेलिया सरकार को जांच शुरू होने के समय स्पष्ट किया था कि उसने भारत को अब यह निर्यात नहीं कर रहा है। इसी कारण, आस्ट्रेलिया यह मानता है कि आस्ट्रेलिया से हुए निर्यात की जांच को तुरंत समाप्त करना चाहिए।

घरेलू उद्योग के विचार

45. प्रस्तुत जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा क्षति से संबंधित निम्नलिखित अनुरोध किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए –

- विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने वर्षों से जांच अवधि में अत्यधिक वृद्धि के साथ काफी वृद्धि दर्शाई है। भारत में उत्पादन और उपभोग में मामले में भी आयातों ने वृद्धि दर्शाई है।
- वस्तुओं की मांग के मामले में उन देशों का बाजार में भी काफी हिस्सा है। जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है इसका कारण संबद्ध देशों से अत्यधिक आयात होना है।
- विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में कमी के साथ भारतीय उत्पादकों के पास केवल एक विकल्प होगा कि वे अपनी कीमतें आयात मूल्य में बदलाव के अनुरूप कम करें अथवा आर्डर और बाजार शेयर छोड़ें।
- घरेलू बाजार में आयातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों का प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा दी जा रही कीमतों पर भी पड़ा है।
- आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योगों की कीमतों में कमी करती रहीं हैं। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में सकारात्मक कमी थी।
- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई थी।
- लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आई थी।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी संबद्ध देशों से गैर-लाभकारी कीमतों पर आयात की मात्रा में भारी वृद्धि होना था।
- आयात की मात्रा में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से कम थी तथा इसलिए पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग पर मूल्य निषेध प्रभाव डाल रहे हैं।
- संबंधित पक्षों के आयात की कम मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर असर के संबंध में यह उल्लेख है कि सभी संबद्ध देशों से 3 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से ऊपर था तथा इसलिए यह कहना गलत होगा कि आयात करते थे। इससे भी अधिक उनका मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री मूल्य से कम है और इस प्रकार क्षति हुई थी। इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि उनके द्वारा उठाई गई क्षति का संबंधित पक्षों के दावे को खारिज किया जाए।
- संबद्ध देशों ने संबद्ध वस्तु के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग ने भारी क्षति उठाई है। साथ ही, यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो, घरेलू क्षति का खतरा बना रहेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. डब्ल्यूटीओ करार के आर्टिकल 3.1 तथा पाटनरोधी नियम के अनुबंध-II में दोनों, (क) घरेलू बाजार में उसी किस्म के उत्पादों के पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ख) इन आयातों का ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर प्रभाव, की गहन जांच का प्रावधान किया है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांचना अनिवार्य है कि क्या भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों की कीमत के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को जांचना अनिवार्य है कि क्या भारत में उसी प्रकार के उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कमी हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक गिराना था, या कीमत वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा काफी हद तक होती।

47. जहां तक घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II के पैरा (iv) इस प्रकार उल्लेख है –

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के अध्ययन में उन सभी आर्थिक घटकों और सूचियों का मूल्यांकन होगा जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं कि जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पाद, बाजार हिस्सा, उत्पादकता निवेश पर लाभ या क्षमता के

उपयोग में स्वाभाविक और संभावित कमी, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव भी शामिल हैं।

48. प्राधिकारी द्वारा यहां दिया गया विश्लेषण प्रस्तुत जांच के दौरान संबंधित पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर निर्णय देता है तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है:

49. इन निवेदनों के संबंध में कि डीजीएडी को न केवल याचिकाकर्ता कंपनी के बल्कि बाजार में मौजूद अन्य घरेलू उत्पादकों को आंकड़ों का भी अध्ययन करना अनिवार्य है, प्राधिकारी के नोट्स में इसका उल्लेख है कि याचिकाकर्ता कंपनी नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की श्रेणी में ही है। साथ ही अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन काफी कम है तथा इसलिए वर्तमान जांच पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

50. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-3 तथा डीजीएडी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षतिरहित कीमत की गणना करता है।

51. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध II(iv) के अनुसार ऐसी तालिकाओं पर विचार किया था जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि उत्पादन क्षमता, उपभोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।

पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव

आयात परिणाम और बाजार हिस्सा

52. पाटित आयातों के परिणाम के संबंध में प्राधिकारी का यह विचार करना अनिवार्य है कि पाटित आयातों में भारी वृद्धि सुनिश्चित है या भारत में उत्पादन या उपभोग के कारण हुई है। क्षति के विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों को आधार बनाया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा निम्नलिखित है –

विवरण	यूओएम	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
संबद्ध देशों से पाटित आयात					
ऑस्ट्रेलिया	मी.ट.	0	0	0	1585
ईयू	मी.ट.	1493	8515	4079	3048
सिंगापुर	मी.ट.	11890	16515	20060	33635
कुल	मी.ट.	13383	25030	24139	38268
अन्य देशों से आयात तथा सिंगापुर से अपाटित आयात	मी.ट.	10593	7594	10985	2040
आयातों की कुल मात्रा	मी.ट.	23976	32624	35124	40308
घरेलू बिक्री	मी.ट.	15370	16615	18192	15533
मांग	मी.ट.	39346	49239	53316	55841
आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देशों से आयात	%	56	77	69	95
अन्य देशों से आयात तथा सिंगापुर से अपाटित आयात	%	44	23	31	5
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	34	51	45	68
अन्य देशों से आयात तथा सिंगापुर से अपाटित आयात	%	27	15	21	4
घरेलू उद्योग	%	39	34	34	28

53. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में जांच अवधि में वृद्धि आधार वर्ष 2009 की तुलना में सुनिश्चित थी। संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष 2009-10 में 13383 एमटी से 38268 मी.ट. तक की वृद्धि हुई थी।

54. समग्र आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 56 प्रतिशत के मुकाबले जांच अवधि के दौरान 95 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कुल मांग में पाटित आयात का बाजार हिस्सा भी 34 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक बढ़ा है। इस प्रकार यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में और साथ ही आयात की मात्रा में और साथ ही आयातों तथा देश में समग्र मांग में भी अत्यंत वृद्धि हुई है।

आयातों का कीमत प्रभाव

55. पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांचना अनिवार्य है कि क्या भारत में ऐसे उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कमी हुई है या क्या ऐसे उत्पादों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी कमी करना था या कीमत वृद्धि को रोकना था जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई थी जो कीमत कम करने, कीमत निषेध तथा कीमत में कमी के संबंध में है।

समय के साथ कीमतों में वृद्धि

56. क्षति की अवधि के दौरान, आयातों की संबद्ध देशों से निर्धारित औसत सीआईएफ कीमतें निम्नलिखित अनुसार है -

संबद्ध देश	पाटित संबद्ध वस्तुओं की (सीआईएफ) निर्यात कीमत	
इकाई	यूएस डॉलर/एमटी	रु./एमटी
2009-10	1768	85381
2010-11	2043	94331
2011-12	2416	116299
12 जनवरी से 12 जनवरी तक (जांच अवधि)	1944	104364

57. उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के सीआईएफ आयात मूल्य वर्ष 2011-12 तक बढ़े तथा उसके बाद कम हुआ था। यह भी देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच अवधि में आयात कीमतों में अमेरिकी डॉलर के सन्दर्भ में काफी गिरावट आई थी। यह देखा जा सकता है कि इसी अवधि के दौरान रूपयों के संदर्भ में भी बदलाव काफी कम है जो कि विनिमय में अंतर का कारण है। प्राधिकारी को न केवल जांच अवधि तथा आधार वर्ष बल्कि समग्र क्षति जांच अवधि के आंकड़ों का अध्ययन करना अनिवार्य है। यह नोट किया गया है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में कीमतों में काफी कमी हुई थी विशेषकर जब उसी अवधि के दौरान लागत में वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उत्तरवर्ती भाग में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

कीमत में कटौती

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयात की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है।

संबद्ध देश	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
पाटित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	90207	99456	120033	106344
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	सूचीबद्ध	100	116	133	128
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	रेंज %	(0 - 10)	0 - 10	(0 - 10)	0 - 10

आस्ट्रेलिया	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
पाटित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	-	-	-	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	-	-	-	***
निवल बिक्री प्राप्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	-	-	-	***
कीमत कटौती (%)	%	-	-	-	***
कीमत कटौती (%)	रेंज %	-	-	-	0 - 10

यूरोपीय यूनियन	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
पाटित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	रेंज%	0 - 10	0 - 10	(5) - 5	0 - 10

सिंगापुर	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
पाटित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	सूचीबद्ध	100	116	133	128
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	रेंज%	(0 - 10)	0-10	(0 - 10)	0 - 10

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था जो जांच अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा की गई भारी कीमत कटौती दर्शाता है। साथ ही, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि जांच अवधि में उनकी कीमतों में कमी हुई है जिसका मुख्य कारण यह है कि उनको अपनी कीमतें पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के बराबर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कीमत कटौती

60. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निर्धारित दर से कम कीमत पर बिक्री की जांच भी की जो इस प्रकार है :-

विवरण	इकाई	आस्ट्रेलिया	यूरोपीय यूनियन	सिंगापुर	संबद्ध देश
पाटित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	रेंज	0-10	0-10	5 - 15	5 - 15

61. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ा था।

कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम या धीमा कर रहे हैं तथा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना था या कीमत वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा काफी बढ़ गया होता। उसके लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमत में परिवर्तन पर विचार किया था।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
पाटित आयातों का पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	90207	99456	120033	106344
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	110	133	118
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	145	153
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	133	128

63. जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में लागत में वृद्धि की तुलना में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमतों में वृद्धि नहीं हुई तथा इसके विपरीत उनमें कमी हुई थी। तदनुसार, यह देखा गया कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

64. पाटनरोधी नियमों का अनुबंध-11 यह अनिवार्य करता है कि क्षति का निर्धारण ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के प्रभाव की वास्तविक जांच के आधार पर होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमों में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का अध्ययन इस आधार पर होगा जिसमें सभी संबंधित आर्थिक घटकों तथा सूचियों का वास्तविक और निष्पक्ष मूल्यांकन हो जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें बिक्री में वास्तविक और संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ तथा क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता भी शामिल है।

65. घरेलू उद्योग से जुड़े विविध क्षति मापदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है :-

- बाजार हिस्सा: घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से तथा घरेलू बिक्री पर पाटित आयातों का प्रभाव निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
घरेलू बिक्री	मी.ट.	MT	15370	16615	18192
संबद्ध देशों से पाटित आयात	मी.ट.	MT	13382	25030	24139
अन्य देशों से आयात और सिंगापुर से पाटित आयात	मी.ट.	MT	21620	21473	25490
कुल आयात	मी.ट.	MT	10594	7595	10985
कुल मांग	मी.ट.	MT	39346	49239	53316
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	Index	100	125	136
मांग में घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा	%	%	39	34	34
मांग में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का हिस्सा	%	%	34	51	45
अन्य देशों से आयात का हिस्सा तथा मांग में सिंगापुर से अपाटित आयातों का हिस्सा	%	%	27	15	21

i. जैसा कि पहले बताया गया है, आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में जांच अवधि में समुचित वृद्धि हुई है। आधार वर्ष 2009-10 में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में 13382 मी.ट. से जांच अवधि के दौरान 38268 मी.ट. की वृद्धि हुई थी।

- लाभप्रदता : निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान कम हुई तथा जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गई थी। यह स्पष्ट दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों का क्षतिपूर्ण प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ा है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	145	153
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	133	128
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	60	-32
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	71	-32

- निवेश पर आय : निम्न तालिका से यह देखा जा सकता है कि निवेश पर आय उसी प्रकार के रुझान दर्शाती है जैसे कि लाभप्रदता तथा जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय नकारात्मक हुई है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	63	-26

यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय नकारात्मक हो गई है।

- नकद प्रवाह : जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का नकद प्रवाह नकारात्मक हो गया हो घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट दर्शाता है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
नकद लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	74	-28

- उत्पादन और क्षमता उपयोग : यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान इस तथ्य के बावजूद कम होता गया कि इसी अवधि में मांग में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने इस आशा से अपनी क्षमता बढ़ाई थी कि मांग में वृद्धि होगी लेकिन पाटित आयातों के क्षतिपूर्ण प्रभाव के कारण वे अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं। यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के पास काफी निष्क्रिय क्षमता है जो बड़ी हुई मांग को पूरा कर सकती है। इसीलिए घरेलू उद्योग को निष्क्रिय क्षमताओं के कारण नुकसान हुआ।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
कुल उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	87	83	74	63
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.ट.	15370	16615	18192	15533

- विक्रियों की मात्रा : उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि 2011-12 तक घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई तथा उसके बाद बाजार आकार में वृद्धि के बावजूद इसमें गिरावट आई। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग की कीमत के स्तर पर भी हानि हुई जिसमें नकद घाटे हुए।
- मालसूची : संबद्ध वस्तुओं की मालसूची के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
इति स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	103	289

66. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया कि जांच अवधि के दौरान अंतिम स्टॉक में आधार वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई थी। जांच अवधि में पिछले दो वर्ष की तुलना में भी वृद्धि के रूझान देखे जा सकते हैं। यह देखा गया कि जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में मालसूची में इस तथ्य के बावजूद वृद्धि हुई थी कि इसी अवधि के दौरान उत्पादन तथा बिक्री कीमत में कमी हुई थी।

- रोजगार और मजदूरी : रोजगार तथा मजदूरी के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार से है :

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
रोजगार	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	100	100	100
मजदूरी/रोजगार (रु०)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	159	171	117
उत्पादन (मी.ट.)	***	***	***	***
उत्पादन/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	106	118	101

- उत्पादकता : उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि में पिछले दो वर्ष की तुलना में उत्पादन के संबंध में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है। इस कमी का कारण संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उत्पादन में कमी था।
- पाटन की मात्रा : पाटन की मात्रा इसका एक सूचक है कि किस हद तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। संबद्ध देशों के प्रति निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर तथा महत्वपूर्ण है।
- पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता : संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति से इस क्षेत्र में भविष्य के निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लाभप्रदता, निवेश पर आय साथ ही घटे हुए नकद प्रवाह में तीव्र कमी दर्शाती है कि इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने में घरेलू उद्योग की क्षमता को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण नुकसान हुआ है।
- घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक : संबद्ध देशों से आयात कीमतों को ध्यान में रखते हुए कीमत ढांचे में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतियोगिता, पाटित आयात के अतिरिक्त कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयात वस्तुओं का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत से काफी कम है तथा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत क्षतिरहित है जिससे कीमत में काफी कमी तथा कम कीमत पर बिक्री हुई। संबद्ध देशों के अतिरिक्त देशों में विचाराधीन उत्पादों का आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि इन देशों द्वारा दी जा रही कीमत काफी अधिक है। इन उत्पादों की मांग वृद्धि के रूझान दर्शा रही है और इसीलिए ये घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे कीमत निषेध के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से पाटित वस्तुएं घरेलू उद्योग की कीमतों में निषेध और कमी की जिम्मेवार हैं।
- वृद्धि : बिक्री, उत्पादन, लाभ, नकद लाभ तथा जांच अवधि में निवेश पर आय के संबंध में मांग में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक रहा था। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने क्षमता वृद्धि के साथ ही लाभ में भारी वृद्धि, सुकर नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय में वृद्धि की आशा की थी। तथापि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग इसे प्राप्त नहीं कर पाए।

झ. वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष :

67. आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव के साथ क्षति के विविध मापदंडों का अध्ययन यह स्पष्ट दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को काफी क्षति हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में वृद्धि हुई तथा साथ ही देश में कुल आयात, घरेलू उत्पादन तथा कुल मांग में भी वृद्धि हुई। अन्य मात्रात्मक मानदंडों जैसे कि घरेलू बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के कारण मात्रात्मक क्षति हुई थी। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के कारण कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया गया कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी कर रहे हैं। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयात के कारण कीमत निषेध का सामना करना पड़ा था क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में वृद्धि नहीं हुई

थी। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों का वस्तुओं के पहुंच मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री प्रकट करती है। लाभ निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह में काफी कमी हुई थी। इस प्रकार घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान काफी क्षति हुई थी।

ट. अन्य ज्ञात कारक तथा आकस्मिक लिंक

68. वस्तु क्षति, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव, इसकी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत निषेध तथा मंदी प्रवाह की उपस्थिति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार तथा भारतीय नियमों के अंतर्गत सूचित अन्य निर्देशक मापदंड की भी समीक्षा यह देखने के लिए की कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में उत्तरदायी थे।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

69. जांच अवधि में संबद्ध देशों के अतिरिक्त देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात कुल आयातों का 3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 2011-12 की तुलना में क्षति अवधि के दौरान निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत से काफी अधिक थी।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयात कीमत (सीआईएफ मूल्य प्रति मी.ट.)					
संबद्ध देशों से पाटित आयात	रुपए/एमटी	85381	94331	116299	104364
अन्य देशों से आयात तथा सिंगापुर से पाटनरहित आयात	रुपए/एमटी	100411	95424	112981	129621

• मांग में कमी तथा उपभोग की पद्धति में बदलाव

70. संपूर्ण क्षति अवधि में संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई। इसलिए घरेलू उद्योग के लिए मांग में कमी क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता।

• प्रौद्योगिकी का विकास :

71. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता।

• विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

72. ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था। चूंकि कच्चे माल तथा संबद्ध वस्तुएं देश में मुक्त रूप से आयात की जा सकती थीं।

• घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन :

73. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था। अतः निर्यात बाजार में निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया था।

• घरेलू उद्योग की उत्पादकता :

74. यह नोट किया गया था कि पिछले दो वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी आई थी जो पाटित आयातों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में कमी के कारण था।

75. यह नोट किया गया कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग को इन कारणों से क्षति उठानी पड़ी थी। किसी भी संबंधित पक्ष ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जो यह बताए कि घरेलू उद्योग को अन्य ज्ञात कारणों से क्षति हुई थी। दूसरी ओर, निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हुई थी।

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात काफी मात्रा में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम कर रही थीं। परिणामतः घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं थे। वास्तव में, घरेलू उद्योग को लागत में

वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अपनी कीमतें कम करनी पड़ी थीं। घरेलू उद्योग जिस कीमत निषेध और कीमत मंदी से प्रभावित है वह मुख्यतः संबद्ध देशों से उत्पाद के पाटित आयातों के कारण है।

- घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों पर दबाव के कारण जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता की काफी हानि हुई तथा निवेश पर नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।
- खराब नकद प्रवाह तथा बढ़ती मालसूची के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ।

76. अतः यह निष्कर्ष निकला है संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को काफी क्षति हुई थी।

छ. क्षति की मात्रा

क्षति मार्जिन

77. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के क्षति रहित निर्धारण की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यात के पहुंच मूल्य से की गई थी। क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे :-

क्षति मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी (अम.डॉ./मी. ट.)	पहुंच मूल्य (अम.डॉ./मी. ट.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ./ मी.ट.)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	***	***	***	***	0 - 10
यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	***	***	***	***	0 - 10
सिंगापुर	कोई	कोई	***	***	***	***	5-15

78. जिस प्रकार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के स्तर निर्धारित किए गए थे वे सार्थक माने गए थे।

ज. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे:

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हैं। पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगी, इसलिए, इससे उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

80. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय खासकर तब जब पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित कर दिया जाए तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन आई कमी को दूर करेगा, और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

झ. **संबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोध**

झ.1 **विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात कथन-अनुरोध**

एसईपीएल तथा एसईटीएल के प्रकटन पश्चात अनुरोध

81. एसईपीएल और एसईटीएल ने प्राधिकारी से अपने निष्कर्ष की संपुष्टि संबद्ध पक्षकारों द्वारा ईक्यूआर न किए जाने, संबद्ध पक्षकारों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति किए जाने, प्रकटन विवरण में इंगित संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में एसईपीएल की भूमिका के आधार पर करने तथा अंतिम जांच परिणाम में भी करने का अनुरोध किया है। एसईपीएल और एसईटीएल ने प्रस्तुत किया है कि शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) एक पृथक निकाय नहीं है परंतु एसईटीएल का एक ट्रेड नेम है और यह एसईपीएल/एसईटीएल की 231 दिसम्बर, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्टों में एसईपीएल/एसईपीएल की एक संबद्ध कंपनी के रूप में उल्लेख नहीं है।

82. एसईपीएल और एसईटीएल ने घरेलू उद्योग के हानि मानदंडों पर अपनी टिप्पणियों पर भी जोर दिया है और प्राधिकारी ने अपने हानि के कारकों से संबंधित इसके अनुरोधों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

बेयर का प्रकटन पश्चात अनुरोध

83. बेयर इस बात को प्रमाणित करता है कि संबद्ध वस्तुओं का केवल *** मी.ट. निर्यात इसके द्वारा भारत को जांच की अवधि के दौरान किया गया है। बेयर का अनुरोध है कि प्राधिकारी इसके आंकड़ों को तभी अस्वीकार कर सकते हैं जब इसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि बेयर ने अपने द्वारा भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की सही मात्रा का प्रकटन नहीं किया है। जहां तक बेयर ने भारत को निर्यातित सही मात्रा की सूचना दी है, इसके आंकड़ों को केवल इस बात के मद्देनजर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है डीजीसीआईएंड एस के आंकड़े आर्कोल पोलिओर 5613 ब्रांड के आयात की अलग मात्रा दर्शाते हैं। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े भी बेयर से आयात की उतनी ही मात्रा को दर्शाते हैं जिसकी सूचना इसके द्वारा निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई है। इस संबंध में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

84. यह केवल इस बात के कारण है कि डीजीसीआईएंडएस बेयर द्वारा सूचना दी गई मात्रा की तुलना में आर्कोल पोलिओर 5613 ब्रांड के आयात की अलग मात्रा दर्शाता है तथा इसके आंकड़े अस्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अस्वीकार किया जाना बेयर की कल्पना से परे है। बेयर प्राधिकारी को इसके आंकड़ों को स्वीकार करने का अनुरोध करता है और एक अलग शुल्क दर प्रदान करता है।

85. चूंकि बेयर एक ज्ञात निर्यातक है अतः एक पृथक पाटन मार्जिन और पाटन का अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार इसके लिए किया जाना है।

86. किसी भी स्थिति में जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, संबद्ध वस्तुओं का निर्माण एसईपीएल द्वारा ही किया जा रहा है और प्राधिकारी ने एसईपीएल के लिए 0 - (10) प्रतिशत तक ऋणात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। अतः संबद्ध जांच शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जानी चाहिए।

मै0 शीला फॉम का प्रकटन पश्चात अनुरोध

87. मै0 शीला फॉम प्रा0 लि0 ने अपने पूर्व के अनुरोधों पर जोर देने के अलावा अपने प्रकटन पश्चात विवरण टिप्पणियों में निम्नलिखित उल्लेख किया है:-

- निर्यात के संबंध में जिसमें शैल द्वारा किया गया निर्यात शामिल नहीं है, हानि मार्जिन के निर्धारण हेतु हमारा अनुरोध है कि शुल्कों का पूर्ण टैरिफ दर पर पहुंच मूल्य के निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे निर्यात में सिंगापुर के साथ आसियान-एफटीए के अंतर्गत रियायती शुल्क नहीं लगता है।
- प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रकार निर्यात मूल्य विभिन्न देशों से अपशिष्ट श्रेणी के लिए तय किया गया है। आवेदक ने कृत्रिम रूप से भाड़ा, वैक प्रभार और अंतरदेशीय ढुलाई में वृद्धि एक्स फैक्टी निर्यात मूल्य में कमी लाने के उद्देश्य से की है। इसके अलावा, कमीशन के रूप में किसी राशि की कटौती का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इनके कारण भी नहीं बताए गए हैं कि क्यों आवेदक के दावे स्वीकार किए गए हैं विशेषकर इस कारण से कि वे किसी साक्ष्य अथवा सबूत के आधार पर नहीं हैं।
- आवेदक ने आवेदन में अनिरंतर/गलत लाभ एवं हानि के आंकड़े दिए हैं। सुरक्षा प्राधिकारियों के समक्ष दायर याचिका में इसने दर्शाया है कि इसका लाभ 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 3 गुना बढ़ गया है। हालांकि वर्तमान याचिका में लाभ में कमी दर्शाई गई है।
- आवेदक का बिक्री मूल्य भी जांच अवधि के पश्चात बहुत अधिक बढ़ गया है। प्राधिकारी ने हानि का विश्लेषण करते समय जांच अवधि के पश्चात के आंकड़ों की जांच नहीं की है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

88. संक्षेप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

- मै0 शैल इस्टर्न कैमिकल्स (एस) ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसलिए इसे सहयोगी निर्यातक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा एसईटीएल ने गलत उत्तर दिया है। इसलिए एसईपीएल और एसईटीएल के पूरे उत्तर को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- एसईपीएल के स्वामित्व वाली पोलिओल संयंत्र के निर्माण क्रियाकलापों का प्रबंधन इसके 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एससीएसएल द्वारा की जाती है और इसलिए यह कहना सही नहीं है कि एससीएसएल संबद्ध वस्तुओं के निर्माण

में शामिल नहीं है। चूंकि एससीएसएल ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए एसईपीएल द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- इस मामले में प्राधिकारी के वर्तमान दृष्टिकोण एआरडब्ल्यू, सोलर और यूएसबी की हाल में की गई जांचों में अपनाए गए दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है जिसमें उत्पादकों द्वारा दायर की गई निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर उत्पादन की पूर्ण मूल्य श्रृंखला के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री का दावा जांच अवधि के दौरान भारत में निर्यात किए जाने के लिए किया गया है।
- प्राधिकारी इस बात का मूल्यांकन करना चाहेगा कि संबद्ध वस्तुओं की लागतें संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी लागत को सही ढंग से दर्शाए। एसएसपीएल से सोर्स किए गए पीओ का मूल्य (ईएलएलबीए के माध्यम से) को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ईएलबीए अपना पी ओ एसएसपीएल के लागत पर स्थानांतरित करता है। इसके अलावा प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रकार से प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि स्थानांतरण मूल्य काफी दूर है और यह उचित रूप में सही लागतों को दर्शाता है।
- आयात मूल्य और न कि पी ओ, संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल का निर्यात मूल्य सिंगापुर के लिए संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से संगत है। इसके अलावा सिंगापुर में पी ओ का निर्यात मूल्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतम निर्यात शैल और बीएएसएफ के संबंधित पक्षकारों को अपेक्षा के सस्ते मूल्य पर चीन और कोरिया में किया गया है।
- पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कोई नई सूचना/दस्तावेज पर सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात विचार नहीं किया जा सकता जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सी आर क्वाइल्स एंड सच्चरिन के संबंध में पाटनरोधी जांच में निर्णय लिया गया है।
- घरेलू उद्योग ने इस बात का उल्लेख किया है कि चूंकि एसईपीएल नामक सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है, 5 प्रतिशत जांच लागू करते समय प्राधिकारी को सिंगापुर से भारत में किए गए कुल निर्यात और न कि केवल शैल के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। आगे यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी को बीएएसएफ और बेयर को घरेलू बिक्री के रूप में की गई बिक्री पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि अंततः इन वस्तुओं का निर्यात भारत में और अन्य देशों में किया गया है।
- प्राधिकारी को एसईपीएल के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य अपनाने के बजाए सिंगापुर में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तय करना चाहिए।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग/एसईपीएल/एसईटीएल/बेयर/ शीला फॉम के उपर्युक्त तर्क पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका समाधान प्राधिकारी द्वारा इनका समाधान प्रकटन विवरण में पहले ही कर दिया गया है। तथापि, प्रस्तुतिकरणों का इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में पुनः समाधान किया जा रहा है।

90. प्राधिकारी के अनंतिम जांच परिणाम की संपुष्टि अंतिम जांच परिणाम में करने के संबंध में एसईपीएल/एसईटीएल के प्रस्तुतिकरण के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण क्रियाकलापों का प्रबंधन एसईपीएल की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी एससीएसएल द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की बिक्री शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस), एसईटीएल के एक पंजीकृत व्यवसाय द्वारा की गई जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री की गई वस्तु का भुगतान शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) द्वारा प्राप्त किया जाता है। यद्यपि एसईपीएल और एसईटीएल ने ईक्यूआर दायर किया है और वहीं दिनांक 12.09.2014 को सार्वजनिक सुनवाई के समय प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद भी शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) ने ईक्यूआर दायर नहीं किया है। संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के अभाव में प्राधिकारी एसईपीएल और एसईटीएल द्वारा दायर ईक्यूआर को नामंजूर कर देते हैं।

91. घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि मैसर्स शेल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस)/एससीएसएल ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और एसईटीएल द्वारा दायर प्रत्युत्तर में गलत ब्यौर दिए गए हैं, प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है और एसईपीएल/एसईटीएल द्वारा दायर प्रत्युत्तर को नामंजूर कर दिया है।

92. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कच्चे की आयात कीमत संगत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विधि के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। सिंगापुर में पीओ का आयात, यूएन कामट्रेड के अनुसार, बहुत ही नगण्य है। अतः प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि सिंगापुर में पीओ की कीमत का निर्धारण करने के लिए सिंगापुर में पीओ की आयात कीमत की तुलना में पीओ की निर्यात कीमत अधिक संगत है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सिंगापुर से चीन और कोरिया को पीओ की निर्यात कीमत पर इस आधार पर विचार न किया जाए कि एसईपीएल/बीएएसएफ एक दूसरे से संबद्ध या समूह निकाय हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया से पीओ की आयात कीमत की तुलना चीन और कोरिया के पीओ की निर्यात कीमत से की है और यह पाया है कि कीमतें तुलनीय थीं। इसलिए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उस कीमत को अपनाया जिसपर पीओ का निर्यात सिंगापुर से संपूर्ण विश्व को किया है।

93. घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि सर्वाजनिक सुनवाई के पश्चात किसी नई सूचना/दस्तावेज पर विचार नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मामले का स्पष्टीकरण करने के लिए प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों सहित घरेलू उद्योग से कोई भी अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज मांग सकते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने तर्क के समर्थन में उल्लिखित जांच में तथ्य एवं परिस्थितियां सकरीन से संबंधित जांच के मामले से भिन्न है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक के संबंधित पक्षकार ने एमईटी और निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर विलंब से दायर किया है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। जबकि वर्तमान मामले में प्राधिकारी एसईपीएल/एसईटीएल द्वारा किए गए दावों के समर्थन में अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज मांगे हैं।

94. क्षति पैरामीटरों के संबंध में एसईपीएल/एसईटीएल की टिप्पणी के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनका समाधान इस अंतिम जांच परिणामों में उपर्युक्त पैराग्राफों में कर दिया गया है।

95. बेयर के इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि उन्होंने संपूर्ण निर्यात भारत को रिपोर्ट किया है और इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बेयर ने सिंगापुर से अपने ब्रांड की संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में अंतर के लिए कोई कारण नहीं दिया है। इसलिए, प्राधिकारी बेयर को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन देने की स्थिति में नहीं है।

96. उतराई मूल्य का परिकलन करने के संबंध में शीला फोम के प्रस्तुतिकरण के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर मूल के सभी आयातों को रियायती शुल्क प्राप्त होगा और इसलिए शेष निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारण करने का अनुरोध नामंजूर किया जाता है।

97. प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

98. घरेलू उद्योग द्वारा लाभ के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना उचित सत्यापन के पश्चात मान ली गई और उस पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

99. पोस्ट पीओआई आंकड़ों की जांच करने के लिए शीला फोम के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि नवीन पाटनरोधी जांच के लिए यह संगत नहीं है।

100. शीला फोम द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनका निराकरण इस जांच परिणाम में संगत पैराओं में कर दिया गया है।

ट. निष्कर्ष :

101. प्रतिरोधी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध तथा उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से इसकी संबद्ध सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है और इस कारण से इस उत्पाद का पाटन हुआ है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के संबंध में पर्याप्त हानि हुई है। पर्याप्त हानि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से हुई है।

ठ. सिफारिशें

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, हानि और कारणात्मक संबंध में पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। पाटनरोधी नियमावली के संबंध में पाटन, हानि और उसके कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई अधिक हानि तथा धनात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन तथा उसके परिणामी क्षति से बचने के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि यह निम्नलिखित निर्धारित रूप तथा तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करे।

103. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे अपनाए जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन और हानि के मार्जिन में से अपेक्षाकृत कम होने के समतुल्य निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हानि होने से बचाया जा सके। तदनुसार नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट राशि के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को संबद्ध देशों में तथा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
•	3907.20	मोलेकुलर वेट का फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल 3000-4000	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	135.96	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	यूरोपीय यूनियन तथा सिंगापुर से इतर अन्य कोई	आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	135.96	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	आस्ट्रेलिया	यूरोपीय यूनियन तथा सिंगापुर से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	135.96	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	यूरोपीय यूनियन	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	154.94	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर से इतर अन्य कोई	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	154.94	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	यूरोपीय यूनियन	आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	154.94	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई	कोई	67.79	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	आस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय यूनियन से इतर अन्य कोई	सिंगापुर	कोई	कोई	67.79	मी.ट.	अम.डॉ.
•	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सिंगापुर	आस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय यूनियन से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	67.79	मी.ट.	अम.डॉ.

104. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

105. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

जे.के.दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2015

(Final Findings)

Sub: Final Findings in the anti-dumping investigation concerning import of “Flexible Slabstock Polyol” originating in or exported from Australia, EU and Singapore.

No.14/1/2013-DGAD:- Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules or the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) received a written application under the Rules from M/s Manali Petrochemicals Ltd., (hereinafter also referred to as the petitioner or the applicant) alleging dumping of Flexible Slabstock Polyol” (hereinafter referred to as FSP or the subject goods) originating in or exported from Australia, European Union (EU) and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries).

2. Whereas the Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 12th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommendation of the anti-dumping duty.

A. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority notified the embassies of Australia and Singapore in India and the Delegation of the European Union in India, representing EU, about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.
- ii. The Authority issued a public notice dated 12th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
- iii. The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties and the industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the Rule 6(2) of the anti-dumping Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. Copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.
- v. Copies of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/producers in the subject countries were also sent to the embassies of Australia and Singapore in India and the Delegation of the European Union in India, along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters/producers from the subject country as also other exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.
- vi. The Authority sent exporter’s questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Antidumping Rules:
 - a. M/s Shell Chemicals, Singapore
 - b. M/s Bayer Polyurethane Asia (PTE) Ltd, Singapore

- c. M/s Bayer Polyurethane Asia (PTE) Ltd, EU
- d. M/s Repsol Quimica, S.A., EU
- e. M/s Dow Chemical (Australia) limited DACL, Australia
- vii. Response to the questionnaire was filed by the following:
 - a. M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (SEPL), Singapore
 - b. M/s Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (SETL), Singapore
 - c. M/s Bayer (South East Asia) Pte Ltd, Singapore
- viii. However, post oral hearing, one of the subject countries, namely, Australia, through its embassy in India, filed written submissions.
- ix. Importer's questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. M/S Sheela Foam P Ltd
 - b. M/S Prime Comforts
 - c. M/S M H Polymers P Ltd
 - d. M/S Somany Foam Ltd
 - e. M/S Tirupati Foam Ltd
 - f. M/S Dura Puf
 - g. M/S Shree Singhal Foams P Ltd
 - h. M/S Multiwyn Foams P Ltd
 - i. M/S Shree Malani Foams P Ltd
 - j. M/S Joy Foam Pvt Ltd
- x. None of the importers filed the importer questionnaire response after the initiation within the time frame. However, post oral hearing one of the importers, namely, M/s Sheela Foam Private Ltd, filed importer's questionnaire response along with their legal submissions.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the period of investigation and preceding three years and the same was obtained and relied upon.
- xiii. The non-injurious price (NIP) has been worked out based on the information furnished by the domestic industry on its cost of production and cost to make and sell the subject goods in India and in the light of the guidelines outlined in Annexure III to the AD Rules. The NIP has been computed so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. Verification of the information provided by the petitioners and the examination of the responses/documentary evidences of the producers/exporters of the subject countries was carried out to the extent considered relevant by the Authority.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in an Oral Hearing held on 12.09.2014. Parties which participated in the Oral Hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- xvi. Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from 1st January, 2012 to 31st December, 2012. The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.
- xvii. The original date for completion of the investigation was up to 11.07.2014. However, at the request of the Authority, this date was extended by the Ministry of Finance up to 11.01.2015.
- xviii. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 03.01.2015. The post Disclosure Statement submissions received, have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

- xix. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Findings Notification.
- xx. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate adopted for the POI is 1 US \$ =Rs 53.69.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

- 4. Responding exporters from Singapore have stated that in the present investigation, the product under consideration only includes Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 but one import transaction in the petition also shows that Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 5000 has been included in the import statistics. The Respondents are apprehensive that there may be many such transactions in the import statistics which would enlarge the import quantity significantly and request the Authority to investigate the same.

Views of the Domestic Industry

- 5. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol, a polymer, originating in or exported from the subject countries. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter.
- 6. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums.
- 7. Flexible Slabstock Polyol is classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.
- 8. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.

Examination of the Authority

- 9. Based on the information submitted by the Domestic Industry and the examination of the material on record, and keeping in view the lack of sufficient evidence of FSP of more than 3000-4000 molecular weight provided by the opposing interested parties, the Authority confirms that the product under consideration as "Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000", falling under code 3907.20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation
- 10. With regard to like article, Rule 2(d) of the anti-dumping rules provides as under:
"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."
- 11. The Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the Indian industry and exported from subject countries. Product under consideration produced by the Indian industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

- 12. The Applicant has claimed in the petition that it is the sole producer of the like article in India. However, M/s Expanded Polymer Systems is another domestic producer of the like article in India. It is surprising to note that the Applicant has not specified their name anywhere in the petition.
- 13. The Authority is required to examine the quantity of the subject product which is or can be manufactured by M/s Expanded Polymer Systems. Additionally, it is also submitted that such information should have been disclosed by the Applicant in the petition and the Authority should appropriately terminate this investigation for want of completeness of petition.

Views of the Domestic Industry

14. The domestic industry submitted that as per the information available with them, they are the only producer commercially producing the subject goods during the period of investigation. In any case, even assuming but not accepting that there are other producers producing the subject goods, M/s Manali Petrochemicals will account for a major proportion of the total domestic production in terms of Rule 2(b) as well as the clear standing in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules.
15. In relation to M/s Expanded Polymers Limited, it is submitted by the domestic industry that they are not in the commercial production of the subject goods.
16. It was further submitted that the present investigation initiated by the Designated Authority is fully in accordance with the Anti-dumping Rules and, therefore, entirely maintainable

Examination of the Authority

17. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: -

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

18. The Application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited. As per the records available with the Authority, the petitioner accounts for major proportion of the product under consideration in the total domestic production in the period of investigation and, therefore, constitutes Domestic Industry as well satisfies the criterion of standing within the meaning of the Rules. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration during the POI by the petitioner or any of its related party within the meaning of Rule 2(b). The petitioner has also certified that it is not related to any of the exporters from the subject countries in terms of the Rules.
19. It is further noted from the evidence on record that the other producer, namely, M/s Expanded Polymers Systems Private Limited, had manufactured negligible quantities of the subject goods during the POI in the total production in the country and even if these negligible quantities are taken into account, it is clear that the standing of the applicant shall not be affected as they would still account for far more than 50% of the total domestic production. Thus, the applicant satisfies the requirements of being considered as the “Domestic Industry” in terms of Rule 2(b) as well the ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules.

D. CONFIDENTIALITY**Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties**

20. Various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
 - i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to petitioner’s policy regarding its distribution channels, commission/discount policy, credit terms, normal value calculation, Purchase Policy, Sales Policy, Inventory and Quality Control Procedure, etc.
 - ii. The Applicant is also registered as a “Public Limited Company”, but has claimed confidentiality over its Annual Reports. No reason has been provided by the Applicant for this claim of confidentiality.

Submissions made by the domestic industry

21. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
 - i. Petitioner has claimed confidentiality on information provided by them as allowed in rule 7 of the AD rules and a meaningful summary of such information was also provided. The claims of interested parties that the petitioner has claimed excessive confidentiality are baseless.
 - ii. On the other hand, excessive confidentiality has been claimed by the exporters inasmuch as the non-confidential versions of the questionnaire response were not the exact replica of the confidential version filed by the exporters as required under the Rules and the instructions on the issue.
 - iii. Information about related entities was kept confidential by Shell group of companies and the Authority had to extract the information from the exporter.
 - iv. Volume related information was also not disclosed by the exporters and same needs to be provided by them.

Shell and Bayers has also not disclosed that their related entities from EU had also exported the subject goods to India but that information is also not provided by them.

- v. One of the two cooperating exporters, namely, M/s BSEA has not even disclosed the names of their linked producers. They have even failed to provide any information in their exporter questionnaire response. Therefore, there is no opportunity for the domestic industry to make any comments.

Examination by the Authority

- 22. Various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules(2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

- ii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. As regards the contention of the opposing interested parties with regard to non-disclosure of the costing information, the Authority has taken the view that costing and price related information is confidential in nature and generally not amenable to summarization. The annual reports of the Domestic Industry are available in public domain and on the website of the applicant. Therefore, the claim of the interested parties regarding excessive confidentiality by the Domestic Industry is not valid and hence rejected. On the other hand, the Authority observes that the Domestic Industry has vehemently contended that Shell Group has not revealed certain basic information relating to their related entities, that they have kept even the volume related information confidential and that most of the appendices in the questionnaire response have not been indexed which could provide a meaningful understanding to the concerned parties. However, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, of the domestic industry and opposing interested parties and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

- 23. The miscellaneous submissions made by the producers/exporters/importers/ other opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. The application filed by the Domestic Industry is not in the form and manner prescribed by the Authority.
 - ii. The application filed by the domestic industry does not even meet the basic evidentiary standard of the Article 5.2 of the Antidumping Agreement.
 - iii. Due to the location disadvantage, domestic industry is facing high logistic costs and, therefore, injury faced by them is on account of poor selection of location and not because of imports of subject goods.
 - iv. Domestic industry is unable to achieve high capacity utilization due to lack of infrastructure to handle critical material like propylene oxide. This factor can also be seen from the various annual reports of the petitioner. Further, due to the moratorium ban domestic industry cannot increase their capacity.
 - v. It is further submitted by one of the importers that the domestic industry is not able to supply subject goods of adequate quality and consistency.
 - vi. Interested parties also contended that there are differences between the petition filed in the anti-dumping and in safeguards investigation. Therefore, the Authority should check and verify the same before coming to any conclusion.

- vii. The domestic industry has not provided any details of average selling price of indigenous product anywhere in Proforma IVB, as per Proforma. Moreover, the indexed numbers in petition are different, which needs to be verified.
- viii. It is relevant that during the POI, the exchange rate for USD that has been adopted by domestic industry is Rs.53.69. However, the prevailing rate of USD, as per the RBI, is currently Rs.61.10. It is also predicted that Rupee will not appreciate once again and may get depreciated further. This means that imports into India currently are priced significantly higher than what they used to be during the POI. It is also submitted that the Applicant Domestic Producers arrived at a price undercutting of 0-10% considering the exchange rate of Rs.53.69. However, if the prevailing exchange rate is considered, which would present the most accurate picture, the level of price undercutting and price underselling would be eliminated.
- ix. Certifications provided by domestic industry are altered by hand. Further, there is no indication of any dates on the certificates.
- x. The Applicant has sought to have safeguard duties imposed on the subject goods, thereby acknowledging that it is suffering injury only due to a certain quantity of imports, and not due to any allegedly dumped imports. This proves that there is no case of dumping of subject goods into India.
- xi. Domestic industry has not provided the excel version of the import data despite the repeated request of the exporters.
- xii. The domestic industry has not provided correct information in relation to difference in production process employed by them and that of exporters.
- xiii. The increase in import volume is because of the positive effect of the India- Singapore CECA. Therefore, the Authority should consider the fact while making any determination.
- xiv. The petition is deficient and, therefore, the investigation needs to be terminated.
- xv. Importers need not file questionnaire response in order to be treated as a cooperating importer. Non-filing or incomplete filing of response does not dilute the right of an interested party to make submissions.
- xvi. Import port data submitted by the domestic industry is not correct as it contain double counting of many import entries.
- xvii. The installed capacity of the domestic industry is 25000 MT, which is about 1/3rd of the total demand in India. The demand supply gap is huge and therefore, the current proceedings should be terminated.
- xviii. Domestic industry is enjoying benefit of trade remedies since 1999 and, therefore, has adversely affected the downstream industry. It was further submitted that the Authority should not recommend duties this time.
- xix. As far as the issue of relationship between BASF and SEPL/SSPL is concerned, the following submissions are made:
 - a) Propylene Oxide (PO) is the main raw material used in the production of Flexible Slabstock Polyol (FSP). SEPL sources PO from, among others, Shell Seraya Pioneer Limited (“SSPL”). SSPL is a 100% owned subsidiary of SEPL. SSPL and BASF South East Asia Pte. Ltd. (“BASF”) jointly own Ellba Eastern Pte Ltd JV (“Ellba”) which is also engaged in the manufacture of PO.
 - b) The applicant has contended during the course of the investigation that BASF and SEPL are related entities as SEPL (as a 100% holding company of SSPL) and BASF jointly own Ellba. The Applicant seeks to support this contention by applying Explanation (c) to Rule 2(b) of the AD Rules, which states that producers shall be deemed to be related to exporters or importers if together they directly or indirectly control a third person.
 - c) Explanation (c) to Rule 2(b), which expressly states that it applies only to Rule 2(b) by the words “for the purposes of this clause” is only applicable to the definition of “domestic industry” contained in Rule 2(b) and not to any other situation. In other words, Explanation (c) to Rule 2(b) cannot be used to support the rather absurd hypothesis that SEPL and BASF are related because they jointly own and control Ellba. Explanation (c) to Rule 2(b) is only applicable to an examination of whether a domestic producer in India and an exporter in a subject country are related to each other. There is no other situation in which Explanation (c) to Rule 2(b) may be applied as it is in the nature of a “legal fiction”, a well known principle of interpretation of statutes.
 - d) The Hon’ble Supreme Court has held in *Bengal Immunity Co. Ltd. v. State of Bihar* AIR 1955 SC 661 that legal fictions are to be limited to the purpose for which it was created and should not be extended beyond that legitimate field.
 - e) This well-settled rule of interpretation has been affirmed in a series of decisions by the Hon’ble Supreme Court, including *CIT, Bombay v. Amarchand N. Shroff* AIR 1963 SC 1448 and *UCO Bank v. Rajinder Lal Capoor*, (2008) 5 SCC 257.
 - f) In light of the above decisions of the Hon’ble Supreme Court, the Designated Authority being a quasi-judicial authority is legally bound to confine the scope of operation of Explanation (c) to Rule 2(b) of AD Rules only to situations where it undertakes an examination of whether a domestic producer in India and an exporter in a

subject country are related to each other. There are no other situations to which Explanation (c) to Rule 2(b) would be applicable, and for the Designated Authority to do so would be in gross violation of its powers and mandate as a quasi-judicial body.

- g) The Respondents thus submit that BASF and SEPL cannot be considered to be related parties by applying Explanation (c) to Rule 2(b) of the AD Rules.
- h) In addition to the above, the Respondents reiterate their consistent submission that BASF and SEPL are not related entities. In support of the same, the Respondents make the following submissions:
 - i. The Designated Authority has considered the same issues earlier in the sunset review of anti-dumping duty against imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from EU, Japan, Singapore and USA and has concluded that BASF and SEPL are not related entities. The relevant extract of Final Findings dated 26th December 2007 is provided below:

“41. BSEA did not have its own FSP manufacturing facility. Propylene is purchased by ELLBA which is a 50-50 joint venture of Shell & BASF and converted into PO. The suppliers bore no legal relation to BASF and propylene is purchased from local as well as overseas suppliers at prevailing market conditions partly on spot basis. BSEA had signed a tolling arrangement with SCSL effective from 2002, whereby BSEA would supply PO to SCSL, which would produce FSP and invoice back the same to BSEA. BSEA could source an increasing amount of FSP, till a final plateau of annual volume was reached, subject to a tolling fee, covering all actual cost and an appropriate rate of return. The arrangement could be terminated 7 years after commencement of the first FSP supply. BSEA sells this finished product as per its own marketing arrangements and under a different brand name. Both SEPL and BSEA are two separate legal entities and have nothing in common except this arrangement.”
 - ii. It may also be seen in Annual Reports for the financial years ending on 31st December 2010, 2011 and 2012 that BASF is not listed as a related company of SEPL. This further proves the fact that SEPL and BASF are unrelated entities and must be treated as such by the Designated Authority.
- xx. In view of the above submissions, the Respondents request the Authority to reject the applicant's argument that BASF and SEPL are related entities due to the fact that SEPL (as a 100% holding company of SSPL) and BASF jointly own Ellba.
- xxi. Australian High Commission submitted that Australia did not receive advice prior to the initiation of the investigation that an application had been received. Further, Australia did not receive advice on the decision to initiate this investigation.
- xxii. Australian High Commission also submitted that it requests to know as to what special circumstances have led to not completing this investigation within one year.

Views of the Domestic Industry

- 24. The domestic industry during the course of the present investigations also raised certain issues and has also given comment on the miscellaneous submissions made by the interested parties, which are as follows:
 - i. Petition is filed as per the guidelines of the Authority by the domestic industry. Further, after being satisfied with the evidences provided by the domestic industry, the Authority has initiated the current investigation and therefore, the current proceedings are valid and justifiable as per current laws.
 - ii. The certificates were signed and submitted prior to initiation of the investigation. The domestic industry nevertheless has confirmed that they were not related to any exporters, importers or they have themselves imported the subject goods in the entire injury investigation period. Further, the concerned person who has signed the certification fully owns and stands responsible for the alteration done by hand. It is therefore submitted that the information provided in the petition is correct and shows no discrepancy as claimed by the interested parties. Further, the domestic industry has followed all the procedures prescribed in the Rules.
 - iii. Domestic Industry has provided complete details of selling price in the Proforma IV A and in the injury analysis. Therefore, mere non reproduction of the information at one place cannot be said as violation of any rule, particularly when the domestic industry has provided price undercutting separately while giving injury analysis.
 - iv. The domestic industry has provided complete raw data to the Authority and explained the segregation methodology in detail, thereafter, the domestic industry has only provides the data relevant for the investigation in the petition. It is also important to note that all the interested parties has made mere submissions and failed to present any evidence to show that the same is incorrect.
 - v. The written submissions filed by M/s Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. (SEPL), M/s Shell Eastern Trading (Pte.) Ltd. (SETL) and M/s Bayer (South East Asia) Pte. Ltd., were not served on us either electronically or by hard copy in terms of the Trade Notice No. 01/2012 dated January 9, 2012. Moreover, M/s Sheela Foams

had not provided any written submissions within the timeline. In view of the aforesaid, the domestic industry requests the Authority to reject the response of interested parties in line with the strict view taken by the Designated Authority in other similar cases where complete response of the exporter has been rejected on account of clerical mistakes.

- vi. Certificates submitted by the exporters/producers are not signed as per the prescribed guidelines of the DGAD. Moreover, complete addresses of all the related parties were also not provided by the exporters in response to the questionnaire sent by the Authority.
- vii. It is submitted by the domestic industry that M/s Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. (SEPL), M/s Shell Eastern Trading (Pte.) Ltd. (SETL) needs to be treated as non-cooperating exporter in line with the view taken by the Designated Authority in the case of Saccharin investigation.
- viii. It is also submitted by the domestic industry that the responses of Shell should be rejected for non-adhering the specific instruction of the Hon'ble Designated Authority of filing complete response of all the related parties to complete the full value chain of the subject goods.
- ix. Shell has also withheld the information that they are related to BASF, one of the exporters of the subject goods. They have also not provided the exact status of their relationship with manufacturers of the major raw material. In view of this factor also, the Authority should reject the complete exporter questionnaire response of the both Shell entities.
- x. Bayer South East Asia (Bayer) has not filed any information in the questionnaire response relating to the linked producer. In the absence of which, Bayer is not entitled to an individual dumping margin. The response is to be rejected outright on this ground alone. Further, it has submitted that the exporter has not even disclosed even the name of the linked manufacturer/producer from which it has purchased the subject goods in the POI for exporting the same to India.
- xi. It is further submitted by the domestic industry that in the event exporter questionnaire response of Shell gets rejected, the exporter questionnaire response of Bayer automatically gets rejected in line with the consistent practice of the Authority. In view of the above, domestic industry has requested the Authority to reject the response filed by the exporter considering the consistent practice being followed by the Authority in plethora of cases.
- xii. Moreover, from the inspection of public file and non-confidential version of the responses submitted by the Shell, it is clear that they have not confirmed that the complete subject goods exported by Bayer is procured domestically from them. In view of the aforesaid, domestic industry submitted that the response of Bayer should also be rejected.
- xiii. The domestic industry can technically produce subject goods up to 50000 MT and there is no constrain in that, except low priced imports coming in the market from subject countries. It is further submitted by the domestic industry that they have advantage of using captively produced propylene oxide (PO) in the manufacturing of subject goods. Moreover, domestic industry is also importing the PO for the balance of their requirement. Therefore, the domestic industry requested the Authority to reject the claims of the interested parties as they are devoid of any merit and contrary of the facts on record.
- xiv. Domestic industry submits that their quality is at par with the imported goods and only because of the low priced imports, user industry is buying imported subject goods. Domestic industry has ample idle capacity to fulfill the local demand.
- xv. In relation to location or geographical disadvantages, domestic industry submits that these factors have no weightage in the anti-dumping investigation as all the expenses after ex-factory are not considered in any of the analysis. Therefore, the argument related to any freight and location disadvantage needs to be rejected.
- xvi. The domestic industry submitted that the history of the previous cases is of no legal or factual relevance to the fact of current proceedings. The Authority is required only to see whether a case for imposition of anti-dumping duties is made out in the facts and circumstances of the present case. It may be appreciated that the interested parties have referred to the details of previous investigations only with the intent to create a bias in the mind of the Authority.
- xvii. In the context of the initiation of the investigation in Safeguard Directorate for the same product, it is submitted by the domestic industry that this is not the first case where both the investigations are going on simultaneously for the same product. Further, it is important to note that in the instant case, the period of investigation is different for both the investigations. Therefore, no prejudice is caused to any interested parties. It is submitted that the Domestic Industry is not seeking duplication of the protection as the Central Government would invariably ensure that only the higher of the two duties is effectively enforced. In view of the aforesaid, the Authority is requested to reject the claims made by the interested parties as they are devoid of any merits. The domestic industry further submits that due to the difference in the methodology used in analyzing the data, there may be some variation in the numbers.

xviii. The domestic industry submits that there is no difference in the production process employed by the domestic industry and producers in the subject countries. Domestic industry further submits that even none of the producers/exporters have provided any information in their exporter questionnaire response. Moreover, they have also failed to provide any material fact to support their claim. In view thereof, the domestic industry requested the Authority to reject the submissions of the interested parties as they are contrary to the facts.

xix. The methodology suggested by the interested parties that the Authority should use current exchange rate and determine price undercutting is wrong and contrary to the established practice of the DGAD.

Examination by Authority

25. Various miscellaneous issues raised by the interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority are examined herein below:

- a. The Authority notes that from the record available with the Authority, the Australian High Commission was duly advised prior to the initiation of the investigation that an application had been received and the public notice initiating the investigation was put on the department's website. Further, the Authority notes that the Rules do provide time up to eighteen months to complete the investigation depending upon the complexity of the responses/submissions.
- b. Regarding the issue raised in the safeguard investigation that domestic industry is suffering injury only due to a certain quantity of imports, and not due to any allegedly dumped imports, the Authority holds that the nature of the safeguard investigations and the anti dumping investigations are two separate and each one is governed by respective rules.
- c. As regards the argument of the opposite interested parties that the petition is deficient and, therefore, the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of prima facie evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and causal link and justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and the Rules. The Authority has also called for additional information wherever required and verified the information furnished by the domestic industry.
- d. With regard to the argument on certificates and support letter, it is noted that the same are complete and correct and has no discrepancy whatsoever.
- e. The information provided by the domestic industry is verified and only verified information is used for the final proceedings of the investigation. It is further noted that the domestic industry has provided all the information as and when required and there is no inconsistency found in their data.
- f. As regards the submission of the interested parties that the increase in imports from Singapore is on account of the FTA between the two countries, it is noted that the argument is of no consequence or relevance from the anti-dumping perspective. As per the anti-dumping rules, anti-dumping duty will only be imposed if the imports are dumped and are causing injury to the Domestic Industry. Therefore, the issues raised by the exporters /importers in relation to increase in imports due to FTA have no bearing in this investigation.
- g. In relation to the import data, it is noted that the Authority has used DGCI&S import data for analysis purpose and, therefore, all the issues related double counting of import data are taken care of.
- h. As regards the argument of using current exchange rate for determining price undercutting, the Authority notes that this would be logically an incorrect proposition. Since the entire investigations relate to a particular period, it would not be appropriate to analyze as effect of exchange rate in isolation for the current period.
- i. As far as the contention of the domestic industry that there is relationship between BASF South-East Asia Pte Ltd ("BSEA") and SEPL/SSPL and BASF has not filed the exporters questionnaire response and, therefore, SEPL/SSPL should be declared non-cooperative, the Authority notes that it has considered the same issues earlier in the sunset review of anti-dumping duty against imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from EU, Japan, Singapore and USA and had concluded that BSEA and SEPL are not related entities. There is no change in these facts in the present investigation as well. The Authority also notes that in the Annual Reports for the financial years ending on 31st December 2010, 2011 and 2012 that BSEA is not listed as a related company of SEPL. This further proves the fact that SEPL and BSEA are unrelated entities and must be treated as such by the Designated Authority. The Authority, thus, concludes that this claim of the applicant is devoid of merit.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value, Export Price and Dumping Margin

26. In the present case, only the following exporters/ producers from Singapore have responded and filed their questionnaire's response in the form and manner prescribed:

- a. M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (“SEPL”)
 - b. M/s Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (“SETL”)
 - c. M/s. Bayer (South East Asia) Pte Ltd (“Bayer”)
27. From their questionnaire responses, the Authority notes that SEPL is involved in production of the subject goods and also manufactures other grades of polyols. SEPL sells the entire quantity of subject goods to SETL, a trading arm of SEPL. SETL is a subsidiary of SEPL. SETL sells the subject goods in domestic market and also to export markets including India. Bayer has also purchased the subject goods for exporting to India from SETL.

Submissions made by the domestic industry

28. The domestic industry has raised a number of issues relating to the questionnaire responses submitted by SEPL/SETL and has requested for rejection of questionnaire responses filed by SEPL/SETL:
- i. The domestic industry has submitted that BSEA and SEPL are related entities as SEPL (as a 100% holding company of SSPL) and BSEA jointly own 50% shares each in a third company, M/s. Ellba Eastern (Pte) Ltd (“ELLBA”). In this regard, the domestic industry has relied on Explanation (c) to Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules which states that producers shall be deemed to be related to exporters or importers if together they directly or indirectly control a third person.
 - ii. The domestic industry has submitted that the responses of Shell Chemical Seraya (Pte) Ltd (“SCSL”), Shell Seraya Pioneer Limited (“SSPL”), Ethylene Glycol Singapore (“EGS”) and Ellba Eastern Pte Ltd JV (“Ellba”) have not been filed, and, therefore, the value chain is not complete. Consequently, the domestic industry has argued that the responses of SEPL and SETL are also to be rejected.
 - iii. The domestic industry has contended that the price at which PO is supplied by SCSL to SEPL should be rejected and the correct market price should be adopted.
 - iv. The domestic industry has contended that the PO supplied by SSPL should be taken at true market value as SSPL is a fully owned subsidiary of SEPL.
 - v. The domestic industry has contended that it is not clear which company is manufacturing the subject goods in Singapore and whether the subject goods are being supplied to Bayer/BSEA by SCSL or SETL.
 - vi. The domestic industry has contended that it is not clear which company owns the manufacturing facilities for the production of the subject goods.
 - vii. The Authority has, in the recently concluded investigation of Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels, taken very strict view and rejected the response of the exporters on the grounds that their value chain is not complete, information of related parties not filed, producer has not confirmed and that the quantity exported by one of the participating unrelated exporter is their goods. In view thereof, domestic industry requested that the Authority should follow the same principle in the instant case also. It is further submitted that any different approach will be contrary to the principles of natural justice.
 - viii. The producer/exporter has misled the Authority by not providing complete costing of their related parties involved in the manufacturing of the major raw material.
 - ix. The local consumption of subject goods in Singapore is only around 1500 MT per annum, which is less than the 5% of the total exports to India during the POI. In this context, it is further submitted that the domestic sales made by Shell which were ultimately exported outside Singapore, should not be considered as their local sales.
 - x. It is also requested by the domestic industry that if Authority is of the view that Shell still deserves an individual dumping margin, then in that case, while computing 80:20 test, the Authority should use international prices of the major raw materials such as propylene oxide and ethylene oxide as the only responding producer from Singapore failed to provide complete details of the costing of raw material of their related parties. It is a well-settled principle of jurisprudence that the prices of raw material which are not at arm’s length ought to be rejected for the purposes of computing the costs.
 - xi. None of the producers/exporters from EU and Australia has participated in the investigation and, therefore, the Authority should construct the normal value and determine the export price as per the consistent practice.
 - xii. All the related companies have not filed the complete exporters’ questionnaire response and, therefore, the value chain is not complete.

- xiii. It is not clear which company is manufacturing the subject goods in Singapore and whether the subject goods are being supplied to Bayer/BSEA by SCSL or SETL.
- xiv. It is not clear which company owns the manufacturing facilities for the production of the subject goods. It is not clear whether the manufacturing facilities for the production of the subject goods are owned by SCSL or SEPL.

Submissions made by SEPL and SETL

29. SEPL and SETL have made extensive submissions on the issues relating to the questionnaire responses submitted by them, as highlighted below:

- i. SEPL and SETL have submitted that BSEA and SEPL cannot be considered to be related merely because of the reason that SEPL and BSEA jointly own ELLBA. Explanation (c) to Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules, which expressly states that it applies only to Rule 2(b) by the words “for the purposes of this clause” is only applicable to the definition of “domestic industry” contained in Rule 2(b) and not to any other situation, as it is in the nature of a “legal fiction”, a well known principle of interpretation of statutes. The Hon’ble Supreme Court has held in the case of *Bengal Immunity Co. Ltd. v. State of Bihar* AIR 1955 SC 661 that legal fictions are to be limited to the purpose for which it was created and should not be extended beyond that legitimate field.
- ii. In the sunset review antidumping investigation findings dated 26th November 2007, the Authority has already concluded under the same set of facts that BSEA and SEPL are independent companies unrelated to each other.
- iii. SEPL is a private limited company incorporated and registered in Singapore. SEPL is a manufacturer of the subject goods in Singapore. SEPL produces the subject goods in its plant.
- iv. The manufacturing activities of SEPL plant are managed by its 100% owned subsidiary M/s. Shell Chemicals Seraya (Pte) Ltd (“SCSL”). Although, SCSL is a separate legal entity, it is treated by SEPL as a fully integrated cost centre, and as a single tax entity with SEPL within Singapore.
- v. The main raw materials required for production of subject goods are Propylene Oxide (“PO”), Ethylene Oxide (“EO”) and Glycerine. PO is the primary raw material used in the production of subject goods (approximately 90% by weight of FSP).
- vi. PO is procured by SEPL from the following companies in the following proportion:

Shell Chemicals Seraya (Pte) Ltd (“SCSL”)	Approx. ***%
Shell Seraya Pioneer Limited (“SSPL”)	Approx. ***%
BASF South-East Asia Pte Ltd (“BSEA”)	Approx. ***%

- vii. In the earlier sunset review against imports of the subject goods, the Authority under the same set of facts had concluded that SCSL was a fully integrated cost centre and there was no rationale in rejecting the cost at which PO was transferred by SCSL to SEPL and adopting the market price of PO.
- viii. The PO supplied by SSPL to SEPL is procured from ELLBA. ELLBA is a 50-50 joint venture between SSPL and BSEA. ELLBA is treated as a cost centre by SSPL. ELLBA transfers PO to SSPL at cost. Thereafter, SSPL transfers PO to SEPL at a transfer price determined on the basis of market price.
- ix. SEPL and SETL have submitted to the Authority all the available information pertaining to SCSL, SSPL, EGS and ELLBA which relates to the production of FSP. Therefore, the contention of the domestic industry that the value chain is not complete is not correct.

Other submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

30. Other submissions concerning normal value, export price and dumping margin made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:
- a. The Applicant domestic producer has sought to have an investigation initiated against the subject goods but have adduced no evidence in support of the same, which has been accepted by the DGAD. In this connection, it is submitted that no investigation is tenable without the fulfillment of the basic evidentiary standards and, therefore, the present investigation must be terminated immediately.

- b. The two conditions specified in the relevant provisions do not include “non-availability” of data relating to domestic selling prices as a ground for construction of normal value. The basis stated in the application for resorting to constructed normal value is thus erroneous.
- c. The estimate of inland freight provided by domestic industry is also not supported by any evidence. The Applicant Domestic Producers have arbitrarily arrived at a set of figures to express its estimation of inland freight. The application did not contain any evidence as to how the figure cited as inland freight was arrived at and what the relevant calculations are.
- d. The normal value and export price arrived by petitioner in its petition cannot be accepted as correct since petitioner has not made available any evidence to support their computations.
- e. The adjustments made by the Applicants with respect to the export price are abnormally high and unsupported by any evidence. Therefore, the Authority should use correct adjustments while computing the export price.

Examination by the Authority

31. In its various submissions, the domestic industry has raised many issues concerning the questionnaire responses filed by SEPL and SETL. The issues which are considered as relevant are being dealt with hereunder:

Relationship between BSEA and SEPL/SETL:

32. As mentioned above, as far as the contention of the domestic industry that there is relationship between BSEA and SEPL/SSPL and BSEA has not filed the exporters questionnaire response and, therefore, SEPL/SSPL should be declared non-cooperative, the Authority notes that it has considered the same issues earlier in the sunset review of anti-dumping duty against imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from EU, Japan, Singapore and USA and has concluded that BSEA and SEPL are not related entities. There is no change in these facts in the present investigation as well. The Authority, therefore, rejects the claim of the applicant in this regard.
33. With regard to the claim of the domestic industry that all the related companies have not filed the complete Exporters' Questionnaire Response (EQR) and, therefore, the value chain is not complete, the Authority notes that the subject goods are claimed to be manufactured by SEPL and sold by SETL. The Authority further notes that the manufacturing operations of the subject goods are managed by SCSL a 100% owned subsidiary of SEPL. The Authority also notes that the sales of the subject goods have been made by Shell Eastern Chemicals (S), a registered business owned by SETL. While SEPL and SETL filed EQR, SCSL and Shell Eastern Chemicals (S) have not filed EQR in spite of a specific direction issued by the Authority at the time of public hearing held on 12.9.2014. In the absence of EQR filed by Shell Eastern Chemicals (S) and SESL, the Authority has not been able to establish (i) the actual export price of the subject goods exported to India, (ii) the actual selling price of domestic sales, (iii) the actual cost of production of the subject goods and (iv) pre and post production movement of the subject goods. Therefore, in the absence of aforesaid complete value chain of production and sale of subject goods, the Authority has rejected the EQR filed by SEPL and SETL.

Determination of Normal Value

34. Under Section 9A (1) (c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under subsection (6), or
 - ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Normal value in the case of producers and exporters from Australia

35. As there is no response from Australia and neither the information concerning the normal value of the subject goods in Australia during the POI has been made available by any interested party, nor could it be accessed in the public domain, the Normal Value for the producers/exporters in Australia is to be determined by the Authority on the basis of international prices of major raw materials and constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and packing cost of the domestic industry by adding reasonable profits. The normal value so determined by the Authority for Australia is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value in the case of producers and exporters from EU

36. As there is no response from EU and the information concerning the normal value of the subject goods in EU during the POI, as prescribed under the Anti-dumping Rules, has not been made available by any interested party, nor could it be accessed in the public domain, the Normal Value for the producers/exporters in EU is determined by the Authority on the basis of international prices of major raw materials and constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and packing costs of the domestic industry by adding reasonable profits. The normal value so determined by the Authority for EU is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value in the case of producers and exporters from Singapore

37. As already mentioned that due to non-filing of EQR by the related parties of SEPL/SETL, the Authority has rejected the EQR filed by them. As there is no other producer of subject goods other than SEPL, the Normal Value for the producers/exporters in Singapore has been determined by the Authority on the basis of international prices of major raw materials and constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and packing costs of the domestic industry by adding reasonable profits. The normal value so determined by the Authority for Singapore is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export price**Export price in case of producers and exporters from Australia**

38. There is no response from any producer/exporter from Australia. In the light of the above, export price from all the producers/exporters in case of Australia is determined on the basis of information available on record. The Authority made adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost as claimed by the petitioner after due adjustment in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level in case of Australia determined is as mentioned in the dumping margin table below.

Export price in the case of producers and exporters from EU

39. There is no response from any producer/exporter from EU. In the light of the above, export price from all the producers/exporters in case of EU is determined on the basis of information available on record. The Authority made adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost as claimed by the petitioner after due adjustment in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level in case of EU determined is as mentioned in the dumping margin table below.

Export price in the case of producers/exporters from Singapore

40. SEPL/SETL had exported the subject goods to several countries in the POI including India through its registered business viz Shell Eastern Chemicals (S). As already mentioned that due to non-filing of EQR by the related parties and due to absence of complete value chain, the Authority has rejected the EQR filed by SEPL/SETL.
41. Bayer had exported ***MT of the subject goods (both in bulk and packed form) to India in their brand name Arcol Polyol 5613 during the POI having total value of US\$ ***. The exporter has claimed adjustments of ***US\$ per MT on account of credit cost, overseas freight, insurance, surveyor fees, cost of drums, drumming cost, warehousing and handling, inland transportation, storage and bank charges. The Authority, however, notes from the import data collected from DGCI&S that about *** MT of Arcol Polyol 5613 has been imported from Singapore where Bayer South East Asia Pte Ltd., is the only trader of Arcol Polyol 5613. Since the quantity of exports reported by Bayer South East Asia Pte Ltd., is materially different from the quantity of imports of their branded subject goods reported in DGCI&S data, the Authority rejects the Exporters Questionnaire response filed by Bayer.
42. Since no other producer/exporter has submitted EQR, the net export price for the exports made from Singapore has been determined on the basis of information available on record. The Authority made adjustments on account of commission, credit cost, bank charges, overseas freight, insurance, inland freight and port handling charges in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level determined is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

43. Considering the normal values and export prices for the subject goods as determined above, the dumping margins for the subject goods have been determined as follows. The dumping margins for the subject goods are as under:

Dumping Margin Table

Country	Producer	Exporter	Normal Value (US\$/MT)	Net Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range %
Australia	Any	Any	***	***	***	***	30-40
European Union	Any	Any	***	***	***	***	30-40
Singapore	Any	Any	***	***	***	***	0 - 10

METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties**

44. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority
- DGAD is required to examine the data of not only the petitioner company but also for the other domestic producers in the market. There is one more producer in the market. That being the case, DGAD should direct petitioners to submit information about the other producers or require other domestic producers to provide necessary information for the purposes of evaluating injury.
 - Import prices have increased during the injury period as compared to base year, therefore, the claim of the petitioner that the dumped and low priced imports are affecting the profitability and its inability to increase selling price has no merit. It is further submitted that there is no volume effect as well.
 - It is submitted that the domestic industry has not fulfilled the requirement with respect to Article 3.4 which mandates that 'actual and potential' decline in various factors be examined and established for a positive finding of injury.
 - The domestic industry has faced injury due to its incapability to expand its plant capacity and also in handling critical raw material and therefore, the injury cannot be said to be because of imports from Singapore.
 - The domestic industry was able to sell 98-99% of the goods produced every year. In that case, inventories with the Applicant Domestic Producer should logically be very low, as opposed to the inflated inventory figures provided in the petition.
 - The domestic industry is alleging that imports of the subject good from subject countries is substantially high and is hampering the functioning of the domestic industry. However, it is to be noted that the domestic industry is only able to cater to 25-30% of the total demand on an average. Even while the capacity utilization of 100%, it was at the most able to cater to about 40% of the total demand.
 - While an Australian sole manufacturer had very minor exports to India of the product under consideration previously, the company has confirmed to Australian Government that at the time of the initiation of this investigation it no longer exported this product to India. For this reason, Australia considers that there must be an immediate termination of the investigation into imports from Australia.

Views of the Domestic Industry

45. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- Imports of the product under consideration have shown significant increase over the years with a significant increase in POI. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India;
 - Market share of the subject countries in demand is significant. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year. The same is due to significant imports from the subject countries;
 - With reduction in the prices by the foreign producers, the only choice available to the Indian producers is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders and hence the market share;
 - Domestic industry prices, reflects the effect of the prices that are being offered by the importers in the domestic market;
 - Imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry. Price undercutting in respect of the product under consideration is positive during the period of investigation;
 - Inventories with the domestic industry increased in the POI as compared with the base year;
 - Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.

- viii. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from the subject countries.
- ix. The increase in selling price was lower than the increase in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- x. As regards the submissions of interested parties that low quantum of imports and their impact of domestic industry, it is submitted that the imports from all the subject countries is above threshold limit of 3% and therefore, it would be wrong to say that imports are miniscule. Moreover, their value is below the cost and selling price of the domestic industry and thus caused injury. Therefore, the Domestic Industry requested the Authority to reject the claims made by the responding interested parties in relation to injury suffered by them.
- xi. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from subject countries. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

Examination by the Authority

46. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
47. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

48. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigations and considered relevant by the Authority:
49. As regards the submissions that DGAD is required to examine the data of not only the petitioner company but also other domestic producers in the market, the authority notes that the petitioner company constitutes domestic industry under the Rules. Moreover, the production of other domestic producer is insignificant and thus cannot have any impact on the current investigation.
50. The Authority computes the non-injurious price in accordance with Annexure 3 to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD.
51. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Volume Effect of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

52. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S Import data. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Imports from subject countries					
Australia	MT	0	0	0	1585

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
EU	MT	1493	8515	4079	3048
Singapore	MT	11890	16515	20060	33635
Total	MT	13383	25030	24139	38268
Imports from other countries	MT	10593	7594	10985	2040
Total Imports Volume	MT	23976	32624	35124	40308
Domestic Sales	MT	15370	16615	18192	15533
Demand	MT	39346	49239	53316	55841
Market share in Imports					
Imports from Subject Countries	%	56	77	69	95
Imports from Other Countries	%	44	23	31	5
Market share in demand					
Imports from Subject Countries	%	34	51	45	68
Imports from Other Countries and undumped imports from Singapore	%	27	15	21	4
Domestic Industry	%	39	34	34	28

53. It is noted from the above table that the imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms in POI as compared to the base year i.e., 2009-10. The imports from subject countries have gone up from 13382 MT in the base year of 2009-10 to 38268 MT during the POI.
54. The market share of imports from subject countries in relation to the overall imports has also gone up significantly from 56% in the base year to 95% during the POI. The increase is significant. Similarly, the market share of imports from subject countries in the total demand has also increased from 34% to 68% during the same period. Thus, it is seen that the volumes from subject countries have increased very significantly in absolute terms as well as in relation to the imports and the overall demand in the country.

Price Effect of Imports

55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Evolution of Prices over the Period

56. In the injury period, average CIF prices of the imports originated in subject countries has been as under:

Subject Countries	Import price (CIF) of dumped subject goods	
	US\$/MT	Rs./MT
Unit		
2009-10	1768	85381
2010-11	2043	94331
2011-12	2416	116299
January 12 to December 12 (POI)	1944	104364

57. It is seen from the above table that the CIF import price of subject goods has increased until the year 2011-12 and decreased thereafter. It is further noted that there is increase in POI as compared to base year. However, the Authority notes that import prices in US \$ terms has considerably declined in the POI when compared to the immediately preceding two years. It may be seen that in rupee terms also the variation is marginal during the

same period due to exchange variation. The Authority is required to examine the data for the entire injury investigation period and not only a comparison of the POI and the base year. It is noted that the decrease in prices as compared to the immediately preceding two years is significant particularly when the costs have gone up during the corresponding period. Detailed analysis has been done in the latter part of the injury analysis.

Price Undercutting

58. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry.

Subject countries	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of dumped imports	Rs./MT	90207	99456	120033	106344
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Index	100	116	133	128
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	Range	(0 - 10)	0 - 10	(0 - 10)	0 - 10

Australia	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of dumped imports	Rs./MT	-	-	-	***
Net Sales Realization	Rs./MT	-	-	-	***
Net Sales Realization	Index	-	-	-	***
Price Undercutting	Rs./MT	-	-	-	***
Price Undercutting (%)	%	-	-	-	***
Price Undercutting (%)	Range	-	-	-	0 - 10

EU	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of dumped imports	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Index	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	Range	0 - 10	0 - 10	(5) - 5	0 - 10

Singapore	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of dumped imports	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Index	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	Range %	(0 - 10)	0-10	(0 - 10)	0 - 10

59. The Authority notes that the landed values of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from subject countries in the POI. Moreover, the Domestic Industry has claimed that their selling prices in POI have declined mainly on account of the fact that they were forced to match their prices with the landed values of dumped imports.

Price Underselling

60. The Authority has also examined the price underselling suffered by the domestic industry during POI on account of dumped imports from the subject countries, as follows:

Particulars	Unit	Australia	EU	Singapore	Subject countries
Landed price of imports	Rs./MT	***	***	***	***
Non-Injurious Price	Rs./MT	***	***	***	***
Price Underselling	Rs./MT	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***
Price Underselling (%)	Range	0-10	0-10	5 - 15	5 - 15

61. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered significant price underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries.

Price Suppression and Depression

62. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. Table below shows the factual position:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed Value of dumped Imports	Rs./MT	***	***	***	***
Index	Indexed	100	110	133	118
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	145	153
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	133	128

63. The selling prices of the subject goods in the domestic market during POI have not increased in comparison to the increase in the cost and on the contrary it has decreased. Accordingly, it is noted that the dumped imports of subject goods from subject countries have suppressed the domestic industry prices.

H. Economic Parameters of the Domestic Industry

64. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
65. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

- i. **Market share:** The effect of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Domestic Sales	MT	15370	16615	18192	15533
Imports from subject countries	MT	13382	25030	24139	38258
Imports from other countries	MT	21620	21473	25490	19501
Total Imports	MT	10594	7595	10985	2040
Total Demand	MT	39346	49239	53316	55841
Trend	Index	100	125	136	142
Market share of Domestic Sales in demand	%	39	34	34	28
Share of imports from Subject countries in demand	%	34	51	45	68
Share of imports from other countries and undumped imports from Singapore in demand	%	27	15	21	4

As mentioned earlier, imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms in POI as compared to the base year, i.e., 2009-10. The imports from subject countries have gone up from 13382 MT in the base year of 2009-10 to 38268 MT during the POI.

- ii. **Profitability:** It can be seen from the table below that the profitability of the Domestic Industry has declined throughout the injury investigation period and become negative in the POI. This clearly shows the injurious impact of dumped imports from the subject countries on the prices of the Domestic Industry.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	145	153
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	133	128
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	60	-32
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	71	-32

- iii. **Return on Investment:** It is noted from the following Table that the return on investment has shown similar trend as that of profitability and the ROI has become negative during the POI.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	63	-26

It is seen that the ROI has become negative during the POI.

- iv. **Cash Flow:** The cash flow for the Domestic Industry has become negative during the POI indicating the decline in the performance of the Domestic Industry.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cash Profit/Losses	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	74	-28

- v. **Production and Capacity Utilization:** It can be seen that the capacity utilization of the Domestic Industry has decreased throughout the injury investigation period despite the fact that demand in the country has increased by 42% during the same period. It may also be noted that the Domestic Industry has increased their capacity anticipating the increase in demand but due to injurious impact of dumped imports they are not able to increase their production. It is also noted that there are significant idle capacity lying with the Domestic Industry to cater to the increasing demand and, therefore, the Domestic Industry has suffered on account of significant idle capacities.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Capacity	MT	18000	20000	25000	25000
Total Production	MT	15573	16510	18381	15703
Capacity Utilization	%	87	83	74	63
Domestic Sales Volume	MT	15370	16615	18192	15533

- vi. **Sales Volumes:** It is seen from the above table that the sales volume of the Domestic Industry has increased till 2011-12 and declined thereafter despite the increase in the market size. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered on the price front also leading to cash losses.

- vii. **Inventories:** The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	66	103	289

66. It is noted from the above table that the closing stock during POI has increased significantly as compared to the base year. The increasing trend can be seen in the POI even when compared to the immediately preceding two years. It is observed that the inventories increased in the POI as compared to the immediately preceding year despite the fact that there was a reduction in the production as well as the selling price during the same period.

- viii. **Employment and Wages:** The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employees	***	***	***	***
Trend	100	100	100	100
Wages/employee (Rs)	***	***	***	***
Trend	100	159	171	117
Production (MT)	***	***	***	***
Production/employee	***	***	***	***
Trend	100	106	118	101

- ix. **Productivity:** It can be seen from the table above that productivity in terms of production per employee has decreased in the POI as compared to the preceding two years. This decline is attributed to the decline in production due to increased dumped imports from subject countries.

- x. **Magnitude of Dumping:** Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and significant.
- xi. **Ability to raise Capital Investment:** The future investment in the sector is marred by the presence of dumped imports from subject countries. The sharp decline in profitability, return on investment along with reduced cash flow indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is jeopardized due to dumped imports from the subject countries.
- xii. **Factors affecting domestic prices:** Considering the import prices from subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value of imported material from subject countries are significantly below the selling price and non-injurious price of the domestic industry causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries are not injuring the domestic industry as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increase trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry. It is thus evident that the dumped goods from subject countries are responsible for the depressed and suppressed prices of the domestic industry.
- xiii. **Growth:** There was negative growth of the domestic industry in terms of sales, production, profits, cash profit as well as ROI in the POI as compared to the base year despite significant increase in demand. The domestic industry has contended that with increase in capacity, the domestic industry had expected robust growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the presence of the dumped imports from the subject countries.

I. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY

67. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports clearly reveals that material injury has been caused to the Domestic Industry during the period of investigation. There is an increase in the volume of imports of subject goods from subject countries during the injury investigation period in absolute terms as well as in relation to the total imports, domestic production and total demand in the country. Other volume parameters like sales, production and capacity utilization of the domestic industry also indicate that the domestic industry has suffered volume injury on account of dumped imports of subject goods from subject countries. With regard to price effect on account of dumped imports of subject goods from subject countries, it is noted that imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price depression on account of imports of subject goods from subject countries. The domestic industry has also suffered price suppression on account of imports of product under consideration from subject countries as sales price of subject goods has not increased in comparison to increase in cost of production of subject goods during the injury period. Comparison of the landed values with the non-injurious price of the Domestic Industry also reveals significant price underselling. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation.

J. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

68. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports from the subject countries on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

(a) Volume and prices of imports from third countries

69. Imports of the product under consideration from countries other than subject countries in the POI are below 3% of the total imports. Further, it is evidenced from the table below that the import prices from other countries were much higher than the import price of imports from subject countries during the injury period except in the year 2011-12.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Import Price (CIF Price)	Rs./MT				
Imports from Subject Countries	Rs./MT	85381	94331	116299	104364
Imports from Other Countries	Rs./MT	100411	95424	112981	129621

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

70. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in demand cannot be a possible reason of injury to the Domestic Industry.

(c) Developments in technology:

71. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is also not a factor causing injury to the domestic injury.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

72. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

(e) Export performance of the domestic industry

73. The Domestic Industry has not exported the subject goods during the injury investigation period. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

(f) Productivity of the Domestic Industry

74. It is noted that the productivity of the domestic industry has declined in POI as compared to the previous two years on account of reduction in the production of the subject goods caused by dumped imports.
75. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. None of the interested parties has also led any evidence to suggest that the material injury caused to the Domestic Industry is attributable to other known factors. On the other hand, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:
- The imports of subject goods from subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was not able to increase its prices commensurate with the increase in costs. In fact, the Domestic Industry had to reduce its prices in the POI as compared to the immediately preceding year despite increase in costs. The price depression and price suppression suffered by the domestic industry is primarily on account of the dumped imports of the product from the subject countries.
 - The pressure on the domestic prices of the domestic industry led to significant loss of profitability and negative return on investment during the POI.
 - Performance of the Domestic Industry also was affected adversely in terms of poor cash flow and rising inventories.
76. It is, therefore, concluded that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports from subject countries.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**Injury Margin**

77. The non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry determined has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin determined are as under:-

Injury Margin Table

Country	Producer	Exporter	NIP (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin Range %
Australia	Any	Any	***	***	***	***	0 - 10
European Union	Any	Any	***	***	***	***	0 - 10
Singapore	Any	Any	***	***	***	***	5 - 15

78. The level of dumping margins and injury margins, as determined, are considered significant.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUE

79. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
80. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES**M.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties****Post-disclosure submissions of SEPL and SETL**

81. SEPL and SETL has requested the Authority to confirm its conclusions on the issue of non-filing of EQR by related parties, supply of raw materials by related parties, the role of SEPL in the manufacture of subject goods indicated in the disclosure statement, in the Final Findings as well. SEPL and SETL submitted that Shell Eastern Chemicals (S) is not a separate legal entity but only a trade name of SETL and it is not figuring in the Annual Reports for the financial years ending on 31st December 2010, 2011 and 2012 of SEPL/SETL as a related company of SEPL/SETL.
82. SEPL and SETL also reiterated their comments on injury parameters of the domestic industry and requested the Authority to re-consider its submissions relating to factors of injury

Post-disclosure submissions of Bayer

83. Bayer certifies that only ***MT of the subject goods has been exported by it to India during the POI. Bayer submits that the Authority can reject its data only if it has evidence that Bayer have not disclosed the correct quantity of subject goods exported by it to India. So long as Bayer has reported the correct quantity exported to India, its data cannot be rejected merely because of the fact that DGCI&S data shows a different quantity of imports of Arcol Polyol 5613 brand. DGCI&S data also shows the same quantity of imports from Bayer as reported by it in its Exporters Questionnaire. There is no discrepancy in this regard.
84. It is only because DGCI&S data shows a different quantity of imports of Arcol Polyol 5613 brand than the quantity reported by Bayer that its data is proposed to be rejected. This kind of rejection by the Authority is beyond the imagination of Bayer. Bayer requests the Authority to kindly accept its data and provide a separate rate of duty.
85. Since Bayer is a known exporter, a separate dumping margin and an individual margin of dumping is to be determined for it by the Authority as per Article 6.10 of WTO Anti-Dumping Agreement and Rule 17(3) of AD Rules.
86. In any case, as admitted by the domestic industry, the subject goods are only being manufactured by SEPL and the Authority has determined a negative dumping margin for SEPL in the range of 0 – (10) %. Therefore, the subject investigation must be terminated at the earliest.

Post-disclosure submissions of M/s Sheela Foam

87. M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., in their post-disclosure statement comments, apart from reiterating their earlier submissions have stated the following:
- For the determination of the injury margin, in respect of exports, other than those effected by Shell, we submit that the full tariff rate of duties are required to be considered for determination of landed value, since such exports would not enjoy concessional duties under the ASEAN - FTA with Singapore.
 - It is not clear from the disclosure statement how Export Price has been worked out for the residual category from the different countries. The applicant has artificially inflated Freight, Bank charges and Inland transportation with a view to reduce the ex-factory export price. There is also no material on record for deduction of any amount towards commission. No reasons have been given as to why the claims of the applicant have been accepted - especially since they are not based on any evidence or material.
 - The applicant has provided inconsistent/incorrect profit & loss figures in the application. In the petition filed before the safeguard authorities, it has shown that its profit has increased three fold in 2011-12 as compared to 2010-11. In the present petition, however, there is a decline in profitability.

- d) The Selling Price of the applicant has considerably increased in the post POI period. The authority has failed to examine post POI data while carrying out injury analysis.

M.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

88. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

- i. M/s Shell Eastern Chemicals (S) has not filed questionnaire response and therefore it should not be treated as co-operative exporter. Further, SETL has filed incorrect response. Therefore, the entire response of SEPL and SETL should be rejected by the Authority.
- ii. The manufacturing activities of the Polyol plant owned by SEPL are managed by its 100% owned subsidiary SCSL and therefore it is incorrect to state that SCSL is not involved in the manufacture of the subject goods. Since SCSL has not filed exporters' questionnaire response, the response filed by SEPL should be rejected.
- iii. The present approach of the Authority in this case is in complete contradiction to the approach in the recent investigations of ARW, Solar and USB, wherein the exporter questionnaire response filed by the producers have been rejected due to absence of complete value chain of production and sale of the subject goods claimed to have been exported to India during the POI.
- iv. The Authority is obliged to evaluate that the costs of subject goods should reasonably reflect the cost associated with production of the subject goods. The price of PO sourced from SSPL (through ELLBA) should be rejected as ELLBA transfers its PO at cost to SSPL. Further, it is not clear from the disclosure statement how the Authority has considered that the transfer prices are at arm's length and reasonably reflective of the true costs.
- v. The import prices and not the export prices of the Propylene Oxide (PO), the main raw material for manufacture of the subject goods are relevant for the purpose of determining constructed normal value for Singapore. Further, the export price of PO in Singapore should not be considered as most of the exports have been made to China and Korea at cheaper prices to the related parties of Shell and BASF.
- vi. No new information/documents submitted by the parties can be considered post-public hearing as had been decided by the Authority in the antidumping investigations concerning CR Coils and Saccharin.
- vii. The domestic industry has stated that since there is only one producer of subject goods in Singapore namely SEPL, while applying the 5% test, the Authority should take into account the total exports to India from Singapore and not the exports of Shell alone. It is further submitted that the Authority should not consider the sales made to BASF and Bayer as domestic sales as ultimately these goods have been exported to India or other countries.
- viii. The Authority should construct the normal value for non-cooperating exporters in Singapore instead of adopting the normal value determined for SEPL.

M.3 Examination by the Authority

89. The Authority has examined the above arguments of the domestic industry, SEPL/SETL, Bayer and Sheela Foams and noted that some of them are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the disclosure statement earlier. However, the submissions considered relevant are being dealt with again in the Final Findings Notification as under:
90. With regard to the submission of SEPL/SETL for confirming the provisional conclusions of the Authority in the Final Findings, the Authority notes that the manufacturing operations of the subject goods are managed by SCSL a 100% owned subsidiary of SEPL. The Authority also notes that the sales of the subject goods have been made by Shell Eastern Chemicals (S), a registered business owned by SETL. It is also noted that the payments for the goods sold are received by Shell Eastern Chemicals (S). While SEPL and SETL filed EQR, SCSL and Shell Eastern Chemicals (S) have not filed EQR in spite of a specific direction issued by the Authority at the time of public hearing held on 12.9.2014. In the absence of complete value chain of production and sale of subject goods, the Authority has rejected the EQR filed by SEPL and SETL.
91. With regard to the submission of domestic industry that M/s Shell Eastern Chemicals (S) and SCSL have not filed questionnaire response and incorrect details are mentioned in the response filed by SETL, the Authority has carefully reconsidered the issue and rejected the response filed by SEPL/SETL.
92. As regards the contention of domestic industry that import prices of the raw material (PO) is relevant for the purpose of determining constructed normal value, the Authority notes that the imports of PO in Singapore as per UN Comtrade data are very negligible as compared to the production of PO in Singapore and its exports to other countries. The Authority, therefore, holds that export price of PO from Singapore is more relevant as compared to the import price of PO in Singapore for the purpose of determining the price of PO in Singapore. The domestic industry has requested not to consider the export price of PO from Singapore to China and Korea on the ground that SEPL/BASF have related or group entities. In this regard, the Authority has compared the import price of PO

from Saudi Arabia with the export price of PO to China and Korea and found that the prices were comparable. The Authority, has therefore, adopted the price at which PO had been exported from Singapore to world for the purpose of constructing normal value.

93. With regard to submission of domestic industry that no new information/ documents can be considered post public hearing, the Authority notes that in order to clarify the matter, the Authority can seek additional information/documents from the interested parties including the domestic industry during the course of the investigation. The Authority notes that the fact and circumstances of the investigations mentioned by the domestic industry in support of their contention are different from the present case as in the investigation concerning Saccharin, the Authority notes that the exporter's related parties had filed the MET and Exporters' Questionnaire response at much belated stage, which were not accepted. Whereas in the instant case, the Authority has sought additional documents/information in support of the claims made by SEPL/SETL in their response.
94. With regard to the comments of SEPL/SETL on injury parameters, the Authority notes that they have been addressed in the relevant paragraphs in this finding.
95. With regard to the submission of Bayer that they have reported the entire exports to India and therefore they should be granted individual dumping margin, the Authority notes that Bayer has not explained the reasons for the variation in the quantity of imports of their branded subject goods from Singapore. Therefore, the Authority is not in a position to grant individual dumping or injury margin to Bayer.
96. With regard to the submission of the Sheela Foam regarding calculation of landed value, the Authority notes that all imports originating from Singapore will enjoy concessional duty irrespective of the exporter and therefore their request for re-determining the injury margin for residual exporters is rejected.
97. The Authority has determined the net export price as per information available on record.
98. The information on profit submitted by the domestic industry has been admitted after due verification and considered for injury analysis.
99. With regard to the request of Sheela Foam for examining the post-POI data, the Authority holds that it is not relevant for the fresh anti-dumping investigation.
100. With regard to the other issues re-iterated by Sheela Foam, the Authority notes that they have been addressed in relevant paragraphs of this finding.

N. CONCLUSION

101. After examining the submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

O. RECOMMENDATIONS

102. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.
103. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table:

S. No.	Heading/Sub-Heading	Description of Goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1.	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Australia	Australia	Any	Any	135.96	MT	US\$
2.	-do-	-do-	Any other than EU and Singapore	Australia	Any	Any	135.96	MT	US\$
3.	-do-	-do-	Australia	Any other than EU and Singapore	Any	Any	135.96	MT	US\$
4.	-do-	-do-	European Union	European Union	Any	Any	154.94	MT	US\$
5.	-do-	-do-	Any other than Australia and Singapore	European Union	Any	Any	154.94	MT	US\$
6.	-do-	-do-	European Union	Any other than Australia and Singapore	Any	Any	154.94	MT	US\$
7.	-do-	-do-	Singapore	Singapore	Any	Any	67.79	MT	US\$
8.	-do-	-do-	Any Other than European Union and Australia	Singapore	Any	Any	67.79	MT	US\$
9.	-do-	-do-	Singapore	Any Other than European Union and Australia	Any	Any	67.79	MT	US\$

104. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

105.101. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J K DADOO, Designated Authority